

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>>

पीएम मोदी के ‘सबके लिए...



प्रथम सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ फोरम 2026 में 43,250 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धताएं

सिंगापुर की कंपनी छत्तीसगढ़ में करेगी निवेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ ने आज भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए सिंगापुर में आयोजित प्रथम सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ फोरम 2026 में 43,250 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकी प्रतिबद्धताएं प्राप्त कीं। इनमें एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस के लिए 41,750 करोड़ रूपए की एक बड़ी निवेश प्रतिबद्धता शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फोरम में राज्य के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जहां छत्तीसगढ़ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के नामांकन पर सहभागिता कर रहा था।

यह महत्वपूर्ण निवेश प्रतिबद्धता सिंगापुर मुख्यालय वाली एनजी कैपिटल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आई है, जो छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट क्षमता का एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करेगी। एनजी कैपिटल ग्लोबल एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ऑन-साइट स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े एआई-रेडी डेटा सेंटर का विकास और वित्तपोषण करती है तथा इसकी उपस्थिति सिंगापुर, भारत, मलेशिया, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में है। मुख्यमंत्री ने फोरम में कंपनी को 'इन्विटेशन



टू इन्वेस्ट' साँपा।

यह निवेश प्रतिबद्धता छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों को और गति देती है। राज्य में पहले से ही भारत का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित है। ये परियोजनाएं मिलकर छत्तीसगढ़ को भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित कर रही हैं।

एनजी कैपिटल ग्लोबल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री स्टानिस्लाव बोरिसोव ने कहा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए

जिस ऊर्जा, भूमि और राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है, वह आज छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। यह एमओयू एक दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत है। हम मध्य भारत में सबसे बड़ा एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस विकसित करने, राज्य में अंतरराष्ट्रीय पूंजी और विशेषज्ञता लाने तथा इसके संचालन के लिए छत्तीसगढ़ के इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर उत्साहित हैं। राज्य को सनस्ट्रीम ग्रीन एनजी प्राइवेट लिमिटेड से

सोलर क्षेत्र के साथ-साथ संबंधित बैटरी स्टोरेज और कंपोनेंट्स के लिए 1,500 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये निवेश प्रतिबद्धताएं छत्तीसगढ़ की नीतियों, संभावनाओं और लोगों के प्रति विश्वास का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के और करीब ले जाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के साथ एक फायरसाइड चैट में भी हिस्सा लिया, जिसका संचालन सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ का पक्ष प्रभावी ढंग से रखते हुए उन्होंने कहा, हम बंद कमरों में चर्चा करके सुधार नहीं लाते। हम सीधे उद्योग जगत से उनकी कठिनाइयों के बारे में पूछते हैं और उसके अनुरूप अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव करते हैं। 450 से अधिक सुधार किए जा चुके हैं और यह 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' तब तक नहीं रुकेगी, जब तक लोग स्वयं यह न कहें कि अब को सुधार की आवश्यकता नहीं है।

फॉर्म-6 पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी नहीं

सीईसी विवाद के बीच सीजेआई सूर्यकांत की अहम टिप्पणी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसने नए वोटरों को रजिस्टर करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी बदले हुए फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी है। कोर्ट की यह टिप्पणी उस विवाद के संदर्भ में आई है जो 2025 में इस फॉर्म में जोड़े गए एक एनेक्चर (अतिरिक्त दस्तावेज़) को लेकर खड़ा हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद पर 28 सितंबर को दिए गए एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा था कि फॉर्म 6 के साथ लगे घोषणा-पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट रिकॉर्ड की जांच करके यह पता लगाना चाहता है कि बदलाव किसने किए हैं। उन्होंने कहा संशोधित फॉर्म 6 को हमने मंजूरी नहीं दी है, यह



बात बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए।

उन्होंने कहा जब रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, तो हम देखना चाहेंगे कि फॉर्म 6 में बदलाव किसने किया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए। बेंच ने कहा कि जब तक जवाब नहीं मिल जाता, तब तक वह यही मानकर चलेगी कि चुनाव आयोग के फैसले कानून के मुताबिक थे। सीजेआई कांत ने कहा रिपोर्ट सही हो सकती है या गलत, लेकिन हम उसके आधार

पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकते... हमें उनके जवाब का इंतज़ार करना होगा। इस विवाद की मुख्य वजह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक अतिरिक्त घोषणा (डिक्लेरेशन) है। इसके तहत नए वोटर्स को एसआईआर प्रक्रिया के दौरान खुद को, या अपने माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी को पिछली वोटर लिस्ट से जोड़ने वाली जानकारी देनी होती है। यह विवाद तब और बढ़ गया जब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस अतिरिक्त ज़रूरत पर आपत्ति जताई थी।

कोयला लेवी घोटाला: देवेंद्र यादव समेत 12 लोगों पर पेश किया

रायपुर। पांच अक्टूबर छत्तीसगढ़ में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा/एंटी कर्प्शन ब्यूरो (ईओडब्ल्यू/एसीबी) ने कथित कोयला लेवी घोटाले में सोमवार को छठा पूरक चालान दाखिल किया, जिसमें कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी जय प्रकाश मौर्य समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। लगभग 10 हजार पन्नों का यह पूरक चालान सोमवार को विशेष न्यायालय में दाखिल किया गया। बचाव पक्ष के वकील फैसल रिजवी ने बताया कि चालान में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है और इनमें से ज्यादातर लोग प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोयला घोटाला मामले में पहले से आरोपी हैं।



उन्होंने कहा कि उनके मुवाकिलों पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और वे अदालत में अपना बचाव करेंगे। चालान में नामजद अन्य आरोपियों में कांग्रेस के पूर्व विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय, पार्टी नेता रामप्रताप सिंह और विनोद

तिवारी, व्यवसायी सुनील कुमार अग्रवाल, पीयूष कुमार साहू, जोगिंदर सिंह, अनुराग चौरसिया, दीपेश टांक और राहुल मिश्रा शामिल हैं। ईओडब्ल्यू ने जनवरी 2024 में ईडी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। ईडी इस कथित घोटाले के धनशोधन पहलू की जांच कर रही है। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान नौकरशाहों, व्यवसायियों, राजनेताओं और बिचौलियों के एक सिंडिकेट ने राज्य में कोयला परिवहनकर्ताओं से कथित तौर पर 25 रुपये प्रति टन की अवैध लेवी वसूली थी। एजेंसियों का आरोप है कि इस सिंडिकेट में सूर्यकांत तिवारी जैसे निजी व्यक्ति तथा पिछली भूपेश बघेल सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव रहें सोम्या चौरसिया और आईएएस अधिकारी समीर विश्‍नोई जैसे सरकारी अधिकारी शामिल थे। आरोप है कि इन लोगों ने कुछ राजनीतिक अधिकारियों के समर्थन से खनिज परिवहन प्रणाली में जानबूझकर बदलाव किए। चालान में कहा गया है कि आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई हाथ से लिखी डायरियों से पता चलता है कि जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयला लेवी के तौर पर लगभग 540 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे।

2030 तक दुनिया मांगे 5 करोड़ अतिरिक्त शिक्षक

नयी दिल्ली। पांच अक्टूबर यूनेस्को ने कहा है कि शिक्षण पेशा डिजिटल प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, समावेशन, प्रवासन और विस्थापन से जुड़ी नयी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके साथ ही, 2030 तक सभी बच्चों को पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दुनिया को पांच करोड़ अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत है। विश्व शिक्षक दिवस पर सोमवार को जारी यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में 10.7 करोड़ शिक्षक हैं और शिक्षकों की स्थिति में सुधार के उपाय तलाशना जरूरी है, ताकि कल के शिक्षित नागरिक सुनिश्चित किए जा सकें।

रिपोर्ट में कहा गया, “शिक्षक हर शिक्षा प्रणाली और अधिक समावेशी, लचीले एवं टिकाऊ समाज के निर्माण के प्रयासों के केंद्र में हैं, लेकिन यह पेशा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच



रहा है। कई जगहों पर शिक्षकों की लगातार कमी, बढ़ती संख्या में शिक्षकों का पेशा छोड़ना और इस पेशे का आकर्षण कम होना, शिक्षकों की भर्ती और उन्हें बनाए रखना लगातार मुश्किल बना रहा है, जबकि उनसे अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं।” इसमें कहा गया, “सतत विकास लक्ष्य-4 को हासिल करने के लिए 2030 तक अनुमानित तौर पर पांच करोड़ अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत होगी। ऐसे में शिक्षकों की

स्थिति और उन्हें मिलने वाले सहयोग को मजबूत करना नीतिगत रूप से तत्काल प्राथमिकता बन गया है।

वर्ष 2030 तक शिक्षकों की मांग का 58 प्रतिशत हिस्सा पेशा छोड़ने वाले शिक्षकों की जगह नए शिक्षकों की भर्ती से पूरा करना होगा।” रिपोर्ट के अनुसार, शोध से पता चलता है कि जिन शिक्षा प्रणालियों में शिक्षकों को बनाए रखने की दर बेहतर होती है और छात्रों के नतीजे अच्छे होते हैं, वहां

शिक्षकों को सार्वजनिक विमर्श और नीतिगत प्रतिबद्धताओं, दोनों स्तरों पर कुशल पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले के रूप में महत्व दिया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया, “शिक्षक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), जलवायु परिवर्तन, समावेशन एवं लैंगिक समानता, पलायन, विस्थापन तथा विभिन्न प्रकार के संकटों और आपात स्थितियों के कारण हो रहे बड़े बदलावों के बीच अपनी भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा प्रणालियां तेजी से हो रहे सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय बदलावों के अनुरूप खुद को ढाल रही हैं।” इसमें कहा गया, “ऐसे में शिक्षकों की भूमिका निभाने की क्षमता केवल शिक्षा में निवेश पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पेशे को मिलने वाली मान्यता, सहयोग और कामकाजी परिस्थितियां भी इसकी प्रतिष्ठा और आकर्षण को प्रभावित करती हैं।

कल भाजपा के सेवा ज्योति कार्यक्रम में शामिल होंगे मोदी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानी में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इन समारोहों की शुरुआत इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले बड़े सेवा ज्योति कार्यक्रम से होगी। भाजपा के एक वरिष्ठ सूत्र के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के 7 अक्टूबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से देश को संबोधित करने की उम्मीद है। दिल्ली भाजपा इस कार्यक्रम स्थल पर लगभग 5,000 लोगों के शामिल होने की तैयारी कर रही है। मुख्य कार्यक्रम से पहले, दिल्ली भर के सभी संगठनात्मक मंडलों से ‘सेवा ज्योति’ जुलूस निकाले जाएंगे, जिनमें बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक हिस्सा लेंगे और फिर स्टेडियम में इकट्ठा होंगे। इस कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष महतोत्रा, रेखा गुप्ता, दिल्ली के सभी सांसद और विधायक, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। पार्टी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत और भी कार्यक्रम तय किए हैं। 8 अक्टूबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली के भारत मंडपम में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे।

वैश्विक शांति और संस्थाओं में सुधार जरूरी : पीए मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड लोकातांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन, बातचीत और कूटनीति के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपना सहयोग जारी रखेंगे। सोमवार को नई दिल्ली के हेटराबाद हाउस में स्विस राष्ट्रपति गाइ परमेलिन के साथ बातचीत के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार को महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड दोनों ही लोकातांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन, बातचीत और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। हम वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत ने शांति की दिशा में हर सार्थक प्रयास का लगातार समर्थन किया है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार आवश्यक है।

आज से महंगी मिलेगी टिकट



नई दिल्ली। हवाई यात्रा महंगी होने वाली है क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, इंडिगो ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए फ्यूल सरचार्ज (ईंधन अधिभार) बढ़ाने का ऐलान किया है। उसने यह फ़ैसला एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) की बढ़ती कीमतों के कारण लिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा लगातार बढ़ती एटीएफ (एयर टर्बाइन फ्यूल) की कीमतों की वजह से इंडिगो को अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट पर फ्यूल चार्ज में बदलाव करना पड़ा है। बदले हुए चार्ज 6 अक्टूबर 2026 को 1 बजे के बाद की सभी नई बुकिंग पर लागू होंगे। अप्रैल के बाद यह दूसरी बार है जब इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। इसे मार्च में लागू किया गया था। दूरी के आधार पर, घरेलू उड़ानों के लिए बढ़ोतरी की रकम 100 रुपये से 350 रुपये के बीच है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की उड़ानों के लिए फ्यूल सरचार्ज 1,000 रुपये से 3,000 रुपये के बीच है।

आदित्य ठाकरे के देश छोड़ने की आशंका, पासपोर्ट जल्दी की मांग

मुंबई। पांच अक्टूबर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने सोमवार को दावा किया कि दिशा सालियान की मौत के मामले को लेकर लगे आरोपों के बीच संभावना है कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधायक आदित्य ठाकरे देश छोड़कर जा चुके हों या हो विदेश जाने की तैयारी कर रहे हों। भाजपा नेता राणे ने यह भी दावा किया कि विधायक आदित्य ठाकरे ने रविवार को मुंबई में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे के नेतृत्व में निकाले गए विरोध मार्च में गिरफ्तारी के डर से हिस्सा नहीं लिया। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक सालियान की आठ जून, 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक आवासीय इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। इसके एक सप्ताह बाद राजपूत बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे, जिसके बाद दोनों मौतों के बीच संभावित संबंध को लेकर अटकलें लगाई गई थीं। शहर की पुलिस ने आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की थी।

उत्तर प्रदेश से भाजपा ने घोषित किए 8 राज्यसभा उम्मीदवार

नयी दिल्ली/लखनऊ। पांच अक्टूबर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए राज्य के मंत्री धर्मपाल सिंह समेत आठ उम्मीदवारों के नामों की सोमवार को घोषणा की। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अगले महीने अपना कार्यकाल पूरा करने वाले अन्य सभी सदस्यों को इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया है। भाजपा ने झारखंड के राज्यपाल एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को बेटी श्रुति गंगवार को भी राज्य से अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के एक बयान के अनुसार, अन्य उम्मीदवार राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत और राम प्रताप सिंह चौहान हैं। बयान में कहा गया कि इन आठ उम्मीदवारों के नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्य से जिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी, बी. एल. वर्मा, अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल और सीमा द्विवेदी, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव तथा बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री वर्मा का नाम भी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं है।

अफित सिंह

बहुजन समाज पार्टी (ब्सक) की प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अपना फ़ैसला बदलते हुए कहा है कि उनके भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। यह फ़ैसला तब आया है, जब कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी में संगठनात्मक बदलाव के तहत आकाश को पार्टी के अहम पद से हटा दिया गया था। माइक्रोब्लॉगिंग साइट डू (पहले दिवटर्) पर हिंदी में किए गए एक लंबे पोस्ट में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आकाश का

व्यवहार और व्यक्तित्व काफी हद तक संतोषजनक रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से पार्टी में कुछ संगठनात्मक बदलाव करने पड़े और अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से रिटायर होना पड़ा। मायावती ने लिखा कि जैसाकि सर्वविदित है कि परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर व उनके परम अनुयायी मान्यवर श्री कांशीराम जी की देश भर में बहुजन-हित हेतु जुबरदस्त त्याग-तपस्या, आजीवन कड़ा संघर्ष व उनके उच्च आदर्श हमेशा ही प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, जिस पर चलकर ही बी.एस.पी. ने देश की राजनीति में अभूतपूर्व सफलतायें अर्जित की हैं और

अब खासकर आगामी यूपी विधानसभा आमचुनाव को लेकर सर्वसमाज के साथ उत्साहपूर्ण जुबरदस्त तैयारी भी की जा रही है। यहाँ यह भी कहना है कि मेरा निजी नहीं बल्कि पूरा 'बहुजन समाज' ही मेरा विराट परिवार है और उनका हित व कल्याण मेरे लिये सर्वोपरि है और हमेशा ही रहेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुये व खासकर पार्टी में अनुशासन बनाये रखने के लिये ही मेरे द्वारा पिछले कुछ दिनों में, अनेकों सबूत फैसेले भी लिये गये हैं और इसको लेकर मेरे अपने भाई-बहन व उनके परिवार के लोग कभी भी अपवाद नहीं रहे हैं, जो कि जग-जगहिर है।



उन्होंने आगे लिखा कि वैसे तो आकाश आनन्द का व्यक्तित्व पार्टी में काफी हद तक ठीक ही रहा है, लेकिन इनको लेकर पिछले दिनों कुछ ऐसे कारण भी रहे हैं जिसकी वजह से पार्टी संगठन में कई बार कुछ ज़रूरी परिवर्तन भी करने पड़े हैं और फिर अन्ततः आकाश आनन्द के ससुर अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से संन्यास लेने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है। जिसके बाद से

आकाश आनन्द के व्यक्तित्व व कार्यशैली आदि में काफी कुछ बदलाव भी लोग देख रहे हैं, जिसका खास प्रमाण पार्टी में वापिसी हेतु अभी हाल ही में सोशल मीडिया 'एक्स' पर किया गया उनका एक पोस्ट भी है, जिसकी काफी चर्चा भी है।

उन्होंने कहा कि इसको लेकर पार्टी के अधिकांश: लोगों का यही कहना है कि आकाश आनन्द के अनुरोध को स्वीकार करते हुये उनकी पूर्व की दी गई जिम्मेवारियों के साथ इनको पार्टी में पुनः कार्य करने का मौका दिया जाये, जिसके लिए इनके पिता के साथ-साथ इनके छोटे भाई ईशान आनन्द ने भी अपनी सहमति जताई है। वास्तव में श्री ईशान

आनन्द ने तो अपनी मिशनरी भावना प्रदर्शित करते हुये यह भी कहा है कि वे बिना किसी पद के ही पार्टी में मा. बहनजी के दिशा-निर्देशन में जो भी आकाश 'एक्स' पर किया गया उनका एक पोस्ट भी है, जिसकी काफी चर्चा भी है।

परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, हालाँकि यह काफी कुछ आकाश आनन्द के ऊपर भी निर्भर करेगा। इन्ही कुछ ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं पार्टी व मूवमेन्ट के हित में आज लिये गये इस फैसले के साथ ही आकाश आनन्द के राजनैतिक उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ ही इनको (आकाश आनन्द) व इनके छोटे भाई ईशान आनन्द को तथा इनके पिता आनन्द कुमार को भी अपना बहुत-बहुत प्यार व आशीर्वाद देती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि पिछले दिनों हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाने के लिए खासकर 'बहुजन समाज' के सभी लोगों का व अपने सभी शुभचिन्तकों आदि का भी मैं पूरे तहेदिल से व सम्मान के साथ उनका आभार भी प्रकट करती हूँ।



फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर में आग, बड़ा हादसा टला

दुर्ग। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित नेहरू नगर में संचालित फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना स्मृति नगर थाना क्षेत्र की है। जिस समय सेंटर में आग लगी उस समय स्टूडेंट्स सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे हालांकि, समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। नेहरू नगर स्थित फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब सेंटर में लगे एक वाटर कूलर से अचानक धुआं उठने लगा। आग लगने की जानकारी मिलते ही कोचिंग प्रबंधन ने बिना समय गंवाए आग पर काबू पाने की कोशिश शुरु की गई। प्रबंधन की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई की वजह से आग को फैलने से पहले ही पूरी तरह बुझा लिया गया। अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता, तो स्थिति गंभीर हो सकती थी, क्योंकि सेंटर में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि आग सिर्फ वाटर कूलर के आसपास तक सीमित रही और समय रहते बुझा दी गई।

अस्पताल के बाथरूम में घुसा खूंखार तेंदुआ, मौके पर पहुंची डीएफओ की रेस्क्यू टीम

कबीरधाम। शहर के पांश इलाके में स्नेहा अस्पताल के बाथरूम में खूंखार तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने बाथरूम के पास एक महिला पर भी हमला कर दिया है। फिलहाल अस्पताल और उसके आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल की वजह से इलाके में लोगों की भारी भीड़ सुबह से ही सड़कों पर नजर आने लगती है। सुबह के वक्त काम पर जाने वाले लोगों और स्कूल का टाइम होने की वजह से ट्रैफिक भी ज्यादा होता है। आज सुबह भी कुछ ऐसा ही माहौल था। तभी एक खूंखार तेंदुआ जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गया।

लोगों की नजर जैसे ही तेंदुए पर पड़ी लोग घबरा गए।आनन फानन में लोगों ने खुद को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया। तभी लोगों ने शोर मचाकर ये बताया कि खूंखार तेंदुआ शहर के बीचो बीच बने स्नेहा अस्पताल के बिल्कुल पास देखा गया है। तत्काल आस पास के दुकानदारों ने अपने यहां लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। इसी बीच स्नेहा अस्पताल के पास लगे एक सीसीटीवी में तेंदुआ नजर आया। तेंदुआ परिसर से छलांग लगाकर बाहर निकलना चाहता था। लेकिन कांच की दीवार होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया और कांच की दीवार से टकराकर गिर पड़ा। कांच की दीवार सटा एक लोहे का गेट था, जिससे तेंदुआ दूसरे प्रयास में वहां से निकल गया।

स्कूल में मधुमक्खियों के काटने से 10 बच्चे घायल

बलरामपुर। जिले के विजयनगर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना में करीब 10 बच्चे घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, बच्चे स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान मधुमक्खियों का झुंड अचानक क्लासरूम में घुसा और बच्चों को काटना शुरू कर दिया। घटना के बाद सभी घायल बच्चों को तत्काल सिविल अस्पताल रामानुजगंज ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की हालत गंभीर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर करने की तैयारी की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। स्कूल में मधुमक्खियों के झुंड के पहुंचने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

कॉलेज पढ़ने वाली युवती पर एसिड अटैक, हालत नाजुक

बालोद। जिले में कॉलेज पढ़ने वाली युवती पर अज्ञात युवक एसिड फेंककर फरार हो गया। एसिड हमले में युवती गंभीर रूप से झुलस गई है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद युवती को रायपुर रेफर किया गया। पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र बालोद की है। एडिशनल एसपी चन्द्रकांत गवर्ना ने बताया, युवती कॉलेज जा रही थी, तभी अज्ञात युवक ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हमलावर तांदुला बांध के जंगलों की ओर भागा है। आरोपी ने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, घायल युवती को तत्काल जिला अस्पताल बालोद ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया जा रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घटना के पीछे की वजह और हमलावर की पहचान का फिलहाल पता नहीं चल सका है।

कांग्रेस ने महतारी वंदन वसूली मीटर के लगाए स्टिकर

तखतपुर। नगर पालिका परिषद तखतपुर क्षेत्र में लगाए गए स्मार्ट मीटर इन दिनों राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गए हैं। स्मार्ट मीटरों पर ‘महतारी वंदन वसूली मीटर’ लिखे स्टिकर लगाए जाने का मामला सामने आया है। इन स्टिकरों पर नगर पालिका परिषद तखतपुर के नाम का भी उल्लेख किया गया है। नगर पालिका तखतपुर में कांग्रेस की सरकार है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटरों पर ये स्टिकर लगाए हैं। कांग्रेस पार्षद और कार्यकर्ता द्वारा स्मार्ट मीटरों का विरोध किया जा रहा है उनका आरोप है कि महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों से स्मार्ट मीटर में बिजली बिल की वृद्धि के माध्यम से बिजली बिल के नाम पर वसूली की जा रही है। इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर, भाजपा पार्षद दल ने इस मामले को लेकर आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। ज्ञापन के जरिए स्मार्ट मीटर लगाने और उस पर लगाए गए आरोपों को लेकर प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष रखा जाएगा।

कांकेर में भालुओं का तांडव ! रात में तोड़े 7 घरों के दरवाजे

कांकेर। जिले के अलग-अलग गांवों में इन दिनों भालुओं की आवाजही से ग्रामीणों में दहशत है। नरहरपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम लारागांव में रविवार देर रात भालुओं ने सात घरों के दरवाजे तोड़ दिए। वहीं, इससे एक रात पहले कांकेर वन परिक्षेत्र के ग्राम सातलोर में एक मादा भालू अपने दो शावकों के साथ गांव में पहुंच गई। मादा भालू शहद की तलाश में पानी की टंकी पर चढ़ गई, जबकि दोनों शावक रातभर गांव की गलियों में घूमते रहे। रविवार देर रात ग्राम लारागांव में अचानक भालुओं की मौजूदगी से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। भोजन और पानी की तलाश में गांव पहुंचे भालुओं ने सात घरों के दरवाजे क्षतिग्रस्त कर दिए। रिहायशी इलाके में लगातार भालुओं के पहुंचने से ग्रामीणों को रात के समय घरों से बाहर निकलने में भी डर बना हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक, भालू भोजन और पानी की तलाश में बस्तियों की ओर आ रहे हैं। देर रात हुई इस घटना के दौरान कुछ लोगों ने भालुओं की गतिविधियों को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया।

घर के बाहर दौड़ते हुए पहुंचा हाथी, बाल-बाल बचा ग्रामीण

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के छहरपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब हाथी रिहायशी इलाके में दस्तक पहुंच गया। इस दौरान हाथी घर से बाहर निकले ग्रामीण के बेहद करीब पहुंच गया। गनीमत रही कि शख्स ने समय रहते हाथी को देख लिया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि एक शख्स अपने घर से बाहर निकलता है। कुछ दुर जाते ही अचानक उसे सामने हाथी नजर आता है। हाथी को इतनी नजदीक देखकर शख्स घबरा जाता है और बिना समय गंवाए पीछे मुड़कर घर की ओर भागने लगता है। इसी दौरान हाथी भी उसकी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण वहां से भागकर अपनी जान बचाता है। अगर वह समय रहते हाथी को नहीं देख पाता तो अनहोनी हो सकती थी। गांव में हाथी के पहुंचने की घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है।

सेवा ज्योति यात्रा 07 अक्टूबर को निकलेगी पदयात्रा

उत्तर बस्तर कांकेर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 07 अक्टूबर को कांकेर में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा में बाइक रैली के साथ पदयात्रा भी निकाली जाएगी। बाइक रैली में लगभग 500 लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही पदयात्रा में भी बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे।

सेवा ज्योति यात्रा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने आज जिला कार्यालय में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की बैठक लेकर आयोजन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने यात्रा के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।



सेवा ज्योति यात्रा में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को 07 अक्टूबर के प्रातः 08 बजे नया बस स्टैंड के पास स्थित डोम में उपस्थित होने कहा गया है।

कलेक्टर द्वारा जिलेवासियों से भी सेवा ज्योति यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अभियान में सहभागिता निभाने की अपील की गई है। समीक्षा

बैठक पश्चात कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ नया बस स्टैंड के पास स्थित डोम में सेवा ज्योति यात्रा के लिए की जा रही तैयारियों का अवलोकन भी किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में श्री महेश जैन, नगरपालिका अध्यक्ष श्री अरूण कौशिक, उपाध्यक्ष श्री उत्तम यादव, श्री राजा देवानी, श्री राजा पाण्डे, जिला पंचायत सीईओ श्री हरेश मंडावी, अपर कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुर्रे, एसडीएम कांकेर श्रीमती सरस्वती बंजारे सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि गण उपस्थित थे।

एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया, बोधघाट परियोजना का कांग्रेस किस आधार पर कर रही विरोध: केदार कश्यप



यात्रा नहीं, बल्कि सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की यात्रा है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक मोदी ने जनसेवा को अपना ध्येय बनाया और दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ाया। मोदी सरकार लगातार गरीब, किसान, महिला, युवा और अन्य सभी वर्गों को सशक्त करने की दिशा में काम कर रही है। 25

करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देश लगातार आगे बढ़ रहा है– केदार कश्यप, वन मंत्री, छत्तीसगढ़ एसआईआर के मुद्दे पर केदार कश्यप ने कहा कि यह संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है। उन्होंने

कांग्रेस और विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर नकारात्मक प्रचार करने का आरोप लगाया।

बीएसपी लोहा चोरी मामले में सीबीआई जांच को लेकर मंत्री ने कहा कि संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है और जांच प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगी।

बोधघाट परियोजना पर उन्होंने कहा कि यह बस्तर की बड़ी परियोजना है। इसमें करीब 100 टीएमसी पानी उपलब्ध रहेगा और इससे 4 से 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने स्वाल उठाया कि जब इस परियोजना का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में भेजा गया था, तो कांग्रेस अब इसका विरोध किस आधार पर कर रही है।

रामानुजगंज के कन्हर नदी से युवक का रेस्क्यू, पुलिस और गोताखोरों ने बचाई जान

बलरामपुर। रामानुजगंज के कन्हर नदी के तेज बहाव में बहे युवक का पुलिस और गोताखोरों की टीम ने सफल रेस्क्यू किया है।आपको बता दें कि साप्ताहिक बाजार के दिन तेज बहाव में बहने की ये कोई पहली घटना नहीं है।इससे पहले भी कन्हर नदी में बहने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मौके पर जब देखा गया तो एनीकट के तीस मीटर आगे युवक फंसा हुआ था।जिसे आसपास के गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक़त के बाद बचा लिया गया है। इसके बाद उसे रामानुजगंज के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कमलपुर गांव के गोताखोरों के सहयोग से युवक को सकुशल बचा लिया गया है। फिर उसे इलाज के लिए रामानुजगंज



शासकीय अस्पताल में भेज दिया गया है। रामानुजगंज कन्हर नदी एनीकट के रास्ते से नदी पार करने के दौरान करीब दो महीने पहले रविवार साप्ताहिक बाजार के दिन एक बुजुर्ग नदी में बहकर लापता हो गया था। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने सर्वे ऑपरेशन बलिया लेकिन बुजुर्ग का शव बरामद नहीं हो सका। अक्टूबर 2025 में कन्हर नदी एनीकट में मछली पकड़ने के दौरान एक युवक नदी में फिसलकर बह गया जिससे युवक की

मौत हो गई थी। अगस्त 2022 में बारिश के मौसम में कन्हर नदी एनीकट को पार करने के दौरान नदी में बहकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। जुलाई 2022 में ही कन्हर नदी एनीकट में नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में बहने से एक मासूम बच्ची की जान चली गई थी। कन्हर नदी एनीकट में चार साल में चार लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। इसलिए बारिश के दौरान एनीकट के रास्ते नदी पार करने की मनाही है। इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए हादसे की शिकार हो रहे हैं।लेकिन इस बार गनीमत रही कि घटना के बाद समय रहते बचाव दल ने रेस्क्यू करके युवक को बचा लिया।

पत्नी की उपस्थिति के बिना तलाक कानून की प्रक्रिया के खिलाफ: छग एचसी

बिलासपुर। फैमिली कोर्ट ने तलाक के मामले में पत्नी को समुचित तरीके से नोटिस दिए बिना एकतरफा फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसे कानून की प्रक्रिया के खिलाफ माना है। जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी ने कहा कि किसी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके खिलाफ आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि एकतरफा फैसले के लिए अखबार में नोटिस प्रकाशित करना अंतिम उपाय है। इससे पहले सामान्य तरीके से नोटिस देने और घर पर चप्पा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। सूरजपुर निवासी महिला के पति ने 9 जनवरी 2024 को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक



का केस फैमिली कोर्ट में पेश किया था। फैमिली कोर्ट ने पत्नी के दिए पते पर पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस सही पता नहीं होने के कारण वापस आ गया। इसके बाद पति ने अखबार में नोटिस प्रकाशित कराने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। 29 फरवरी 2024 को स्थानीय अखबार में नोटिस प्रकाशित हुआ। पत्नी का कहना था कि उसे तलाक की कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। उसे 18 नवंबर 2024 को औरंगाबाद में चल

रहे भरण-पोषण के मामले की काउंसलिंग के दौरान तलाक की डिक्री की कॉपी दिखाई गई। इसके बाद उसने प्रमाणित प्रति हासिल की और 2 दिसंबर 2024 को एकतरफा तलाक की डिक्री रद्द करने की अर्जी दायर की। पारिवारिक न्यायालय ने 25 अप्रैल, 2024 को पारित एकतरफा तलाक के फैसले को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ करने की महिला की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद महिला ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। हाई कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के नियम 17 और 20 का हवाला देते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट ने केवल एक बार नोटिस वापस आने के बाद सीधे अखबार में प्रकाशन का आदेश दे दिया।

कुरुद तहसील कार्यालय में एसीबी की रेड

धमतरी। जिले के कुरुद तहसील कार्यालय में सोमवार को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्ततखोरी के आरोप में एक सरकारी कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया।



बताया जा रहा है कि कुरुद एसडीएम कार्यालय की भू-अर्जन शाखा में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ पुनेश्वर सूर्यवंशी के खिलाफ रिश्तत मांगने की शिकायत एसीबी को मिली थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक जमीन की खरीदी-बिक्री से जुड़े मामले में डायवर्जन की प्रक्रिया के नाम पर पुनेश्वर सूर्यवंशी ने 20 हजार रुपये रिश्तत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले की जांच की और शिकायत को सही पाए जाने के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। तय योजना के मुताबिक शिकायतकर्ता प्रकाश चंद्राकर को रिश्तत की रकम देने के लिए भेजा गया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी पुनेश्वर सूर्यवंशी को 10 हजार रुपये की रिश्तत की रकम दी, उसी दौरान एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। टीम ने आरोपी के कब्जे से रिश्तत की रकम बरामद कर ली है। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी सहायक ग्रेड-3 पुनेश्वर सूर्यवंशी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। मामले में रिश्तत की मांग से लेकर रकम लेते रंगे हाथ पकड़े जाने तक की पूरी कार्रवाई की जानकारी जुटाई जा रही है

सब्जियों की फसल के बीच गांजे की खेती पुलिस ने 112 पौधे किए जन्म, आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर। बलरामपुर जिले में सब्जियों की खेती लहलहाते अवैध गांजे पौधे पकड़ा गया है। पटवारी की सूचना पर पुलिस ने खुखुरी के रखैतपारा में दबिश दी। यहां से 112 नग गांजे के पौधे जन्म किए गए, जिसकी कीमत 3 लाख से अधिक की बताई जा रही है। पुलिस को ग्राम खुखुरी के रखैतपारा क्षेत्र में गांजे की अवैध खेती किए जाने की सूचना मिली थी। यह सूचना पटवारी के माध्यम से पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर जांच की।

पुलिस के मुताबिक, 3 अक्टूबर, शनिवार को खुखुरी के हल्का पटवारी ने पुलिस को सूचना दी कि कबीर साय टेकाम ने अपनी जमीन के सब्जियों के फसल के बीच मदक पदार्थ गांजा लगाया है। इसके बाद विरछ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम रवाना किया गया। पूछताछ में कबीर साय ने घर के



बाड़ी में सब्जी के फसल के बीच गांजा की खेती करना कबूल किया।

मौके से पुलिस ने सब्जी फसल के बीच में लगाए गए मादक पदार्थ गांजा का छोटा बड़ा पौधा, डगाल, हरा पत्ता, तना सहित कुल 112 नग पौधा बरामद कर पंचनामा तैयार किया। कुल 36 किलो 300 ग्राम गांजा पकड़ाया, जिसकी कीमत 3 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई। मामले में पुलिस ने आरोपी कबीर साय टेकाम को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

संक्षिप्त समाचार

प्रिंस ढाबा तोड़ने पहुंची प्रशासन की टीम संचालक ने खुद पर उड़ला पेट्रोल

रायपुर। राजधानी रायपुर के सड़ू स्थित प्रिंस ढाबे में सोमवार को उस समय गहमागहमी की स्थिति बन गई, जब प्रशासन की टीम बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ ढाबे को अवैध बताकर तोड़ने पहुंची। इस दौरान ढाबा संचालक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया, जिसके बाद प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए कार्रवाई को स्थगित कर दिया। प्रशासन द्वारा ढाबे को अवैध बताते हुए तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान ढाबा संचालक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। मुख्य विवाद ढाबे की जमीन के सीमांकन को लेकर सामने आया। ढाबा संचालक ने आरोप लगाया कि बिना सीमांकन किए ही प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। संचालक का यह भी आरोप है कि मामला कोर्ट में विचारगारण होने के बावजूद प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर मौके पर अधिकारियों और ढाबा संचालक के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। कार्रवाई के विरोध में ढाबा संचालक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया और आग लगाने की कोशिश की, जिससे हड़कंप मच गया। स्थिति को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। इस मामले में तहसीलदार का कहना है कि कोर्ट का ऑर्डर आने तक कार्रवाई को स्थगित किया गया है।

7-8 अक्टूबर को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन

रायपुर। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा 7 एवं 8 अक्टूबर 2026 को राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में और कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब की अध्यक्षता में आयोजित इस रोजगार मेले में तकनीकी एवं गैर-तकनीकी क्षेत्रों के 8 हजार से अधिक रिक्त पदों पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सचिव कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग ड. बसवराजू एस. ने बताया कि द्वारा रोजगार मेले में प्रदेश के वृद्ध उद्योगों एवं निजी प्रतिष्ठानों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्त पदों के लिए युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। इच्छुक युवा ई-रोजगार पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों को जानकारी प्राप्त करने के साथ रोजगार मेले के लिए अपना पंजीयन भी करा सकते हैं। राज्य एवं जिला स्तरीय रोजगार मेलों में चयनित आवेदकों को कार्यक्रम के दौरान ऑफर लेटर प्रदान किए जाने की भी तैयारी की गई है।

दुर्ग स्टेशन पर किलाबंदी, टिकट चेकिंग के 246 मामलों से 1,59,870 राजस्व प्राप्ती

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ सुस्कर विपुल विलासराव के निर्देश पर दुर्ग रेलवे स्टेशन पर किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों, 12 ट्रेनों में किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान में कुल 246 मामलों को दर्ज कर 1,59,870 रुपए राजस्व प्राप्त किया गया। किलाबंदी टिकट चेकिंग में बिना टिकट यात्रा करने वाले 150 यात्री पकड़े गए, जिससे 1,26,125 राजस्व प्राप्त हुआ। अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वाले 39 यात्रियों से 25745 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ, अधिक लोग लेकर यात्रा करने वाले 55 यात्रियों से 6000 रुपये, 2 केस स्टेशन परिसर में कचरा फैलाने वाले से 2000/- रुपए राजस्व प्राप्त हुआ। इस टिकट चेकिंग का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को टिकट लेने के प्रति जागरूक करना था। इस टिकट चेकिंग अभियान में सहायक वाणिज्य प्रबंधक श्री अविनाश कुमार आनन्द, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक टिकट चेकिंग 1 एवं 18 टिकट चेकिंग स्टाफ स्टाफ शामिल रहे।

महिला चेम्बर की आम सभा आज, महिला आयोग की अध्यक्ष होंगी मुख्य अतिथि

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महिला चेम्बर द्वारा मंगलवार को शाम 5 बजे न्यू बॉम्बे मार्केट स्थित चेम्बर भवन में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया है। चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौराना के कुशल मार्गदर्शन एवं महिला चेम्बर अध्यक्ष डॉ. इला गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित यह कार्यक्रम महिला नेतृत्व, सशक्तिकरण और व्यापारिक विकास पर केंद्रित रहेगा। जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। महिला चेम्बर की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. इला गुप्ता, प्रदेश महामंत्री मनीषा तारवानी और प्रदेश कोषाध्यक्ष नम्रता अग्रवाल ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उन्हें नई संभावनाओं से जोड़ना है।

दुर्ग से मांढर तक 70 किलोमीटर पर स्टैंडर्ड कवच कमीशन

रायपुर/बिलासपुर। भारतीय रेल में आधुनिक तकनीक के माध्यम से रेल संरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। दुर्ग से मांढर तक 70 किलोमीटर के सभी रेल मार्गों सहित सरोना-उत्कुरा बाईपास लाइन पर स्टैंडर्ड कवच की कमीशनिंग 3 अक्टूबर को पूर्ण की गई। इस परियोजना के अंतर्गत 984 ट्रैकसाइट आरएफआईडी टैग्स को अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था के साथ स्थापित एवं प्रोग्राम किया गया है।

राजधानी/छत्तीसगढ़

विश्व पर्यावास दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में छत्तीसगढ़ पुरस्कृत

प्रधानमंत्री मोदी के सबके लिए आवास के संकल्प को छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता से कर रहा साकार : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों को किफायती एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों और प्रभावी कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। ईडब्ल्यूएस-एलआईजी वर्ग के लिए भूमि आरक्षण तथा एएचपी (साझेदारी में किफायती आवास) के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के लिए भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया है।

विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की ओर से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा तथा राज्य शहरी विकास अधिकरण (सुदा) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी-सह-राज्य मिशन संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सुमित अग्रवाल ने सम्मान ग्रहण किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए आवास की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही उन्हें बेहतर नागरिक सुविधाओं से



युक्त सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा आवासीय परियोजनाओं की स्वीकृति, भूमि की उपलब्धता, निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता तक प्रत्येक स्तर पर प्रभावी निगरानी की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में छत्तीसगढ़ की कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए भूमि आरक्षण तथा एएचपी के माध्यम से किफायती आवास उपलब्ध कराने की हमारी पहल को मिली यह पहचान राज्य सरकार की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और परिणामोन्मुख कार्यशैली का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबके लिए आवास के संकल्प को

छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहा है। पक्का घर केवल चार दीवारें और छत नहीं, बल्कि एक परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे और जरूरतमंद परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त बेहतर आवास उपलब्ध हो।

शहरी क्षेत्रों में गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए आवास निर्माण की सबसे बड़ी चुनौतियों में भूमि की उपलब्धता प्रमुख रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस चुनौती के समाधान के लिए निजी कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए भूमि आरक्षण के प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप राज्य में 25 हजार 413 आवासों के निर्माण के लिए बिना सरकारी खर्च के भूमि उपलब्ध हुई है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत 17 हजार 790 और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 7 हजार 623 आवास शामिल हैं। इस पहल की विशेषता यह है कि कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए आवास केवल शहरों के बाहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहकर

कांग्रेस की दिल्ली में बैठक पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा का तंज

■ कहा- एसआईआर का जब एक बार विरोध हो चुका है, तब फिर क्यों विरोध?

रायपुर। दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस की होने वाली बैठक पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र काफी सालों से वैसा ही है। ये समय-समय पर अपना रंग गिराफिट की तरह बदलते रहते हैं। जब एसआईआर होना था, तब विरोध हुआ। जब विरोध हो चुका है तो फिर क्यों विरोध? हकीकत यह है कि भारत 1947 में आजाद हो चुका है, लेकिन इनके ऊपर से



गुलामी का साया अभी तक नहीं हटा है।

भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में युवा कांग्रेस चुनाव में आपसी खींचतान को लेकर कहा कि तत्कालीन सरकार में शराब घोटाले का पैसा बराबर नहीं बंटा था, उसी का परिणाम है कि आपसी खींचतान जारी है। वहीं कांग्रेस प्रभारी सुखदेव

भगत के छत्तीसगढ़ दौरा पर कहा कि एक बार आए थे, मैं उनका स्वागत कर चुका हूं। बार-बार छत्तीसगढ़ आये। इससे हमारी रणनीति मजबूत होगी।

वहीं कोल लेवी मामले में पेशी को लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जिन लोगों के खिलाफ प्रकरण है, उनके खिलाफ चालान पेश किया जा रहा है। अब जांच और कार्रवाई के अनुरूप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब चालान पेश होगा, तब पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी।

गरबा में उसे नहीं जाना चाहिए, जो मूर्ति पूजा नहीं करता: मंत्री अग्रवाल

रायपुर। गरबा में मुस्लिम युवकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात विभिन्न संगठन कर रहे हैं। इस बीच छग वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम रिजवी के गरबा में मुस्लिम युवकों के नहीं जाने और जाने पर मां-बहन को साथ ले जाने वाले बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। इस बयान का संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल समर्थन किया है, तो वहीं दूसरी ओर इस बयान पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है। गरबा आयोजनों को लेकर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि गरबा, देवी माँ के आराधना का पर्व है। उस व्यक्ति को कार्यक्रम में नहीं जाना

चाहिए जो नहीं मानता हो, मूर्ति पूजा नहीं करता हो। किसी को जाने का शौक है तो अपनी माँ और बहन को साथ लेकर जाए।

उन्होंने कहा कि बदमाशी 5 लोग करते हैं, और बदनाम पूरा समाज होता है। दोनों समाजों के बीच वैमनस्यता बढ़ती है। ऐसी घटनाओं को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है उस कार्यक्रम में जाए ही नहीं। मंत्री राजेश अग्रवाल के बयान पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी त्योहार को भी बांटने का काम कर रही है। बीजेपी वालो को तो शर्म करना चाहिए। कह रहे मुस्लिम को अपनी मां बहन लेकर जाना चाहिए, तो क्या सारे हिन्दू अपनी मां-बहन को लेकर गरबा में जाते है?

कोयला घोटाला : आरोपी पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, विनोद तिवारी के साथ कोर्ट पहुंचे विधायक देवेंद्र यादव

■ कहा- न्यायालय पर पूरा भरोसा, पर सरकार पर नहीं

रायपुर। कथित कोयला घोटाला में आज आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की स्पेशल कोर्ट में आरोपियों को समन जारी किया था। मामले में आज अंतिम चालान पेश किए जाने की संभावना है। कोर्ट पहुंचने के दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, लेकिन प्रदेश की सरकार प न तो जनता को भरोसा है, और न ही उन्हें। लंबे समय की जांच के बाद अब चार्जशीट पेश की जा रही है। उन्होंने



सरकार को कुशासन की सरकार बताते हुए कहा कि वे कांग्रेस और राहुल गांधी के सहाथी हैं, और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जेल की सलाखें भी पहले उनका हौसला नहीं तोड़ पाई, ऐसे में यह षड्यंत्र उनका हौसला क्या तोड़ेगा।

वहीं चिंतामणि महाराज को लेकर भी देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच की शुरुआत में चिंतामणि महाराज का नाम एफआईआर में प्रमुखता से था, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद

उनका नाम ही गायब हो गया। ये बीजेपी की स्कीम है, बीजेपी में शामिल होने के बाद मामले खतम हो जाने का यह जीता-जागता उदाहरण है।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी प्रकरण साल 2020 से बहुरचर्चित कोयला परिवहन पर लगाया गया अवैध शुल्क था। जांच एजेंसियों के अनुसार, राज्य में ऑनलाइन ई-परमिट प्रणाली में बदलाव कर मैनुअल अनापत्ति प्रमाण पत्र व्यवस्था लागू की गई थी। इसके तहत खदानों से कोयला निकालने और उसके सुचारु परिवहन के एवज में प्रति टन 25 रुपए की दर से अवैध वसूली (कोल लेवी) करने के अनेक समानांतर सिंडिकेट खड़ा किया गया था। इस



करने की घोषणा की गई है।

संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा ने बताया कि नर्सिंग स्टाफ का ग्रेड पे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर 2018 में आंदोलन किया गया था। आंदोलन के दौरान नर्सों को जेल में ठूस दिया गया था। कठोर यातनाएं दी गई थी, जिसके पश्चात नर्सों की लंबित मांगों के निराकरण के लिए शासन द्वारा कमेट्री गठन कर ग्रेड पे बढ़ाने संबंधी अनुशंसाएं की गई थी,

लेकिन वह अनुशंसा आज 8 साल बीत जाने के बावजूद लागू नहीं की गई। उन्होंने कहा, नर्सों ने विगत कई वर्षों से लिखित, मौखिक अनेक निवेदन और पत्राचार मंत्रियों अधिकारियों से किया है,

शहरी गरीबों के आवास के लिए केवल योजना बनाने तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीन की उपलब्धता से लेकर किफायती घर के निर्माण तक प्रभावी व्यवस्था विकसित की है। ईडब्ल्यूएस-एलआईजी वर्ग के लिए भूमि आरक्षण और एएचपी मॉडल को राष्ट्रीय सम्मान मिलना इसी कार्य का परिणाम है। साव ने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि शहरों में जरूरतमंद परिवारों को तेजी से सम्मानजनक और किफायती आवास उपलब्ध हों। यह राष्ट्रीय सम्मान पूरी टीम को और बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित करने के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ता है।

राज्य सरकार की इस पहल से 25 हजार से अधिक शहरी गरीब एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होने की दिशा में आगे बढ़ा है। निजी कॉलोनियों में भूमि आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन ने एक ओर आवास निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता को बड़ी चुनौती का समाधान किया है, वहीं दूसरी ओर समाज के कमजोर वर्गों को विकसित शहरी क्षेत्रों और बेहतर नागरिक सुविधाओं से जोड़ने का रास्ता भी बनाया है। विश्व पर्यावास दिवस पर मिला यह राष्ट्रीय सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबके लिए आवास के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता, नवाचार और परिणामोन्मुख कार्यप्रणाली की राष्ट्रीय पहचान है।

ग्रेड-पे बढ़ाने की मांग, नर्सिंग स्टाफ 7 से करेंगे चरणबद्ध प्रदर्शन

रायपुर। प्रदेशभर के स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ ने ग्रेड पे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। एसोसिएशन के मुताबिक 7अक्टूबर 2026 से चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। पहले चरण में 7 अक्टूबर को भोजन अवकाश के दौरान प्रदेश के ब्लॉक और जिला स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम का जापन अपने संस्था प्रमुख तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा।

आंदोलन के अगले चरण में 30 अक्टूबर 2026 को राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय धरना-प्रदर्शन और महारैली प्रस्तावित है। एसोसिएशन ने बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ के इस प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही है। वहीं, मांगों पर समाधान नहीं होने की स्थिति में 18 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू

लेकिन एक भी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। मांगों के निराकरण न होने की दशा में 2023 में भी नर्सों द्वारा छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले आंदोलन किया गया। फिर भी कोई निराकरण नहीं हुआ। बदले में 2500 से भी अधिक कर्मचारियों को निर्लंबन और बर्खास्तगी की सजा भुगतनी पड़ी थी। ऐसे में अब प्रदेशभर के स्टाफ नर्स और नर्सिंग सवर्ग के कर्मचारी निराश और आक्रोशित होकर आंदोलन का रुख करने को विवश हो रहे हैं। नर्सों ने इस बार स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर इस बार ग्रेड पे में वृद्धि नहीं की गई तो 30 अक्टूबर को प्रदेशभर की नर्सों राजधानी में विशाल महारैली का आयोजन करेंगे। दिवाली तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो उसके बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज होगा। इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। इसकी सूचना सरकार को दे दी गई है।

छत्तीसगढ़ के जंगलों को ग्लोबल टूरिज्म मॉडल से जोड़ेंगे साय

सिंगापुर के मंडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म की व्यवस्थाएं देखीं

रायपुर/सिंगापुर। छत्तीसगढ़ के जंगलों और वन्यजीव संपदा को वैश्विक पर्यटन से जोड़ने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सिंगापुर के मंडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व का दौरा किया। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक आवास के प्रबंधन और पर्यटक सुविधाओं की आधुनिक व्यवस्था का अवलोकन किया। साय ने कहा कि सिंगापुर के अनुभवों से सीख लेकर छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप इको-टूरिज्म का ऐसा मॉडल विकसित किया जा सकता है, जिसमें संरक्षण के साथ पर्यटन और रोजगार को भी गति मिले।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी के साथ मंडाई वाइल्डलाइफ रिजर्व का दौरा कर वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म की व्यवस्थाएं देखीं। साय भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के नामांकन पर सिंगापुर में आयोजित प्रथम सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ फोरम 2026 में भाग लेने पहुंचे हैं।

छत्तीसगढ़ की करीब 44 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र



है। बस्तर से सरगुजा तक फैले जंगल, समृद्ध जैव-विविधता और राष्ट्रीय उद्यान-अभयारण्य राज्य को इको-टूरिज्म के लिए विशिष्ट आधार देते हैं। सरकार अब इन प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर पर्यटक सुविधाओं और स्थानीय भागीदारी से जोड़कर पर्यटन को नई संभावनाएं तलाश रही है।

मंडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक परिवेश में वन्यजीव संरक्षण, पर्यटकों के

छुटे हुए व नये मतदाता पात्रों के लिये चुनाव आयोग का विशेष अभियान

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, जिले में छूटे हुए एवं नए पात्र युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य छूटे हुए पात्र नागरिकों के साथ-साथ ऐसे युवा एवं पहली बार पात्र बने मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है, जिनके नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। यह कार्य बीएलओ द्वारा घर-घर भ्रमण कर मतदाता सूची के निर्धार अद्यतनीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा सभी पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सम्मत पात्र नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और मतदाता सूची में अपना पंजीकरण विधिवत सुनिश्चित करें।

मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करने के लिए ईसीआईएनईटी मोबाइल एप्य या वेबसाइट <https://voters.eci.gov.in> के माध्यम से फॉर्म 6 में ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

ट्रम्प की दादागिरी को नियंत्रित करना लाजिमी

प्रो. दरबारी लाल

विश्व की सर्वोच्च संसद संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 81वें अधिवेशन में शांति, सुरक्षा और विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विदेश मंत्री और प्रतिनिधि अपने भाषणों द्वारा प्रदेश दे रहे हैं। शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनके भाषण ही भविष्य की दशा और दिशा तय करते हैं। इस समय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 90 देश युद्ध ग्रस्त हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने विश्व के देशों की दरपेश गंभीर समस्याओं और संकट उत्पन्न करने वाली चुनौतियों को देख कर भी नजरअंदाज किया और अपने भाषण में ईरान को आतंकवादी देश कहा और यह धमकी दी कि वह नए सिरे से अमरीका से समझौता करे या सर्वनाश के लिए तैयार हो जाए और अपने व्यक्तिगत कारनामों की बखूबी चर्चा की। हकीकत में उनका भाषण आक्रामकता, नकारात्मकता और विध्वंसात्मकता की ओर इशारा करता है। ट्रम्प ने महासभा में खुद को शांति का मसीहा होने का दावा किया कि उसने 8 युद्ध ग्रस्त देशों को अपनी टैरिफ नीति से बचा लिया है और यदि वह ऐसा न करते तो इन देशों में 30 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा बैठते। जबकि हकीकत यह है कि वह न तो रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करवा सके, जो पिछले 4 वर्षों से भारी जानी-माली नुकसान के साथ लगातार जारी है और न ही इसराईल और अन्य हथियारों की जबरदस्त समय पर करा सके, जिसके कारण गाजा पट्टी में रहने वाले 70,000 से अधिक लोग मारे गए। दूसरे देशों के युद्ध बंद करने में तो कामयाब नहीं हुए, बल्कि अमरीका ने खुद ही इसराईल के साथ मिलकर ईरान पर खुली बमबारी की, जिसमें हजारों लोग मारे गए। 1,31,000 ईमरतें धराशायी हो गईं। राष्ट्रपति ट्रम्प का यह ढींग मारना कि उनके पास गोला-बारूद का इतना भंडार है, जिससे वह सालों तक लड़ाई लड़ सकते हैं और उन्हें नए हथियारों के निर्माण की जरूरत नहीं है। जबकि उनकी अपनी पेंटागन की अगस्त महीने की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अमरीका में हथियारों और गोला-बारूद की कमी का संकट पैदा हो गया है। उनके पास करूज मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल और अन्य हथियारों की जबरदस्त कमी हो गई है। मीडिया के अनुसार इस कमी के कारण अमरीका ने ईरान से युद्ध बंद किया है और इसी कारण नाटो देश भी यूक्रेन की सहायता करने में असहाय हो जाएंगे, जिसका फायदा रूस उठाने में चूक नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने अमरीका और वेनेजुएला के तेल को मिलाकर विश्व का 60 प्रतिशत तेल के मालिक होने का दावा किया है, जबकि सर्वे के अनुसार दोनों देशों के पास केवल 22 प्रतिशत तेल है। सारा विश्व जानता है कि वेनेजुएला अमरीका का न तो कोई प्रदेश है और न ही उसका इस पर कोई संवैधानिक और कानूनी अधिकार है, बल्कि वेनेजुएला एक संप्रभुता सम्पन्न राष्ट्र है और अमरीका ने उसके राष्ट्रपति को अपने पास बंदी बना रखा है और उसकी तेल कम्पनियों से अमरीकी तेल कंपनियां तेल खरीद कर दूसरे देशों को बेच रही हैं। वेनेजुएला सरकार किसी भी समय बगावत कर सकती है। ताजुब यह है कि अन्य शक्तिशाली देश न तो बाहर से और न ही यू.एन. में वेनेजुएला की सम्प्रभुता के हक में खुल कर समर्थन कर रहे हैं। भारी टैरिफ से अमरीका में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। जिससे ट्रम्प की लोकप्रियता में कमी आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन से बड़े-बड़े हिमखंड तेजी से पिघल रहे हैं। यदि ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण न किया गया तो भविष्य में नदियों के जल में अत्यधिक कमी आ जाएगी। भारत को भविष्य में अधिक सर्तक रहने की जरूरत है, क्योंकि इस बार यू.एन. में कश्मीर पर पहले तुर्की ने और फिर पाकिस्तान ने राग अलापा है।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय 14-दर्शनों में आस्तिक और नास्तिक का भेद

गताक्त से आगे...

साधारणतया आस्तिक ईश्वर के मानने वाले को कहते हैं और नास्तिक ईश्वर के न मानने वाले को। परन्तु यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त विभाग में यह अर्थ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आस्तिक कहलाने वाले दर्शनों में जो सकत से कम दो पूर्वमीमांसा और सांख्य स्पष्ट रूप से ईश्वर को नहीं मानते, और वेदान्त का ब्रह्मवाद भी यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय ईश्वर के सिद्धान्त का निषेध ही है। शेष तीन दर्शनों में, अर्थात् योग, न्याय और वैशेषिक में ईश्वर को माना तो गया है, परन्तु उनकी आन्तरिक दार्शनिक प्रक्रिया में ईश्वर के लिये कोई स्थान नहीं है, केवल अलग से अर्थात् बाह्य रूप में मानों मानने की दृष्टि से ही ईश्वर को स्थान दिया गया है जैसा कि आगे दिखाया जायगा। इसलिये यह स्पष्ट है कि ईश्वर का मानने और न मानने की दृष्टि से दर्शनों का यह आस्तिक नास्तिक विभाग नहीं बनता। वास्तविक बात यह है कि वैदिक

सम्प्रदायों के लोग %आस्तिक% उन्हें कहते थे जो वेदों को सर्वोपरि प्रमाण मानते हों। इस दृष्टि से 6 वैदिक दर्शन आस्तिक दर्शन हैं और बाकी चार्वाक, जैन, और बौद्ध नास्तिक दर्शन हैं। वे वेदों को प्रमाण नहीं मानते ।

परन्तु गम्भीर विचार करने से यह स्पष्ट हो जायगा किं वेदों को मानने, न मानने के आधार पर आस्तिक और नास्तिक का भेद निराधार है, वस्तुत: पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से आस्तिक शब्द का अर्थ है कि जो है (अस्ति) यह मानता हो वह आस्तिक और जो नहीं है (नास्ति) ऐसा मानता है वह नास्तिक। है या नहीं है यह परलोक की दृष्टि से कहा जाता है अर्थात् परलोक है या नहीं। उसका वास्तविक तात्पर्य केवल यह है कि अपने बुरे और भले कर्मों का अर्थात् धर्म और अधर्म का फल मानना आस्तिकता है; दूसरे शब्दों में यह कि धर्म और सत्य की व्यवस्था अथवा धर्म के आदर्शों में विश्वास रखना. **क्रमश: ...**



दक्षिण चीन सागर में जिनपिंग ने खेला बड़ा खेल

नीरज कुमार दुवे

दक्षिण चीन सागर में विस्तारवाद की दिशा में आगे बढ़ते हुए चीन अब समुद्र के बीच अपनी सैन्य ताकत का ऐसा किला खड़ा करने में जुटा हुआ है, जो आने वाले दिनों में पूरे हिंद-प्रशांत के सामरिक समीकरण को हिला सकता है। ताजा उपग्रह तस्वीरों से हुए खुलासे से पता चला है कि विवादित पैरासेल द्वीपसमूह के एंटीलोप रीफ पर चीन तेजी से रनवे और विशाल सैन्य ढांचे का निर्माण कर रहा है। इस कदम ने उसके इरादों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, यह निर्माण पूरा होने के बाद यहां से लड़ाकू विमानों, निगरानी विमानों और अन्य सैन्य संसाधनों के संचालन की क्षमता विकसित की जा सकती है। यानी चीन समुद्र के बीच एक और ऐसा ठिकाना तैयार कर रहा है, जहां से वह अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर अपनी सैन्य शक्ति को तेजी से आगे बढ़ाने की स्थिति में होगा। साफ है कि बीजिंग दक्षिण चीन सागर को सिर्फ अपने प्रभाव का क्षेत्र नहीं, बल्कि सैन्य शक्ति के विस्तार का विशाल मंच बनाने की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह रनवे 2027 के मध्य तक परिचालन में आ सकता है।

तस्वीरों में मिट्टी समतल करने, बजरी और कंक्रीट डालने तथा भारी निर्माण मशीनों की गतिविधियां साफ दिखाई देती हैं। एक लदा हुआ बजरा नवनिर्मित घाट की ओर जाता हुआ भी देखा गया है। चीन ने आधिकारिक तौर पर इसे सैन्य अड्डा नहीं माना है और सरकारी माध्यमों ने इसे मौसम पूर्वानुमान, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अन्य नागरिक उद्देश्यों से जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन जिस पैमाने पर निर्माण हो रहा है, वह इस परियोजना के संभावित सामरिक उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

हम आपको बता दें कि एंटीलोप रीफ कोई सामान्य समुद्री निर्माण परियोजना नहीं है। यह पैरासेल द्वीपसमूह में स्थित है, जिस पर चीन के साथ



वियतनाम और ताइवान भी दावा करते हैं। चीन ने 1974 में दक्षिण वियतनाम की सेनाओं को पैरासेल क्षेत्र से हटाकर वहां अपना नियंत्रण स्थापित किया था और तब से इस क्षेत्र पर उसका कब्जा बना हुआ है। यदि यहां सैन्य श्रेणी का रनवे और पूरा अड्डा तैयार हो जाता है तो चीन के युद्धक विमानों, निगरानी विमानों और नौसैनिक शक्ति की पहुंच दक्षिण चीन सागर के उत्तरी हिस्से में काफी बढ़ सकती है। इससे चीन को अपने परमाणु-सक्षम पनडुब्बी बेड़े वाले हैनान द्वीप के आसपास के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और निगरानी मजबूत करने में भी मदद मिल सकती है।

हम आपको बता दें कि चीन पहले ही स्प्रेटली द्वीपसमूह में फिएरी क्रॉस, मिसचीफ और सुबो रीफ पर बड़े रनवे, बंदरगाह, निगरानी और वायु रक्षा सुविधाएं विकसित कर चुका है। अब पैरासेल क्षेत्र में निर्माण उस व्यापक रणनीति का आला चरण दिखाई देता है, जिसमें बीजिंग समुद्र के भीतर अपनी स्थायी सैन्य पहुंच और निगरानी का जाल मजबूत कर रहा है। तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती। एंटीलोप रीफ के निकट यागोंंग द्वीप पर भी कई संरचनाएं दिखाई दी हैं। अगस्त में सामने आई उपग्रह तस्वीरों के आधार पर कुछ विश्लेषकों ने वहां संभावित रडार या प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जैसी संरचनाओं की संभावना जताई थी, हालांकि उनके वास्तविक उपयोग की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

ज्ञान/मीमांसा

एसआईआर: लोकतंत्र की शुचिता और विश्वास की कसौटी

ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसका मतदाता है और मतदाता की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पहचान उसका मताधिकार है। इसलिए मतदाता सूची केवल नामों का प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। जिस व्यक्ति का नाम पात्र होते हुए मतदाता सूची में नहीं है, उसकी लोकतांत्रिक भागीदारी अमूरी रह जाती है और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो, जो स्थानांतरित हो गया हो अथवा जिसका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हो, उसका नाम सूची में बने रहना चुनाव की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े करता है। इसी दृष्टि से मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है। लेकिन इसकी सफलता केवल गलत या अपात्र नाम हटाने से नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सुरक्षित रखने और छूटे हुए मतदाताओं को वापस जोड़ने से तय होगी। निर्वाचन आयोग ने 2026 में एसआईआर की प्रक्रिया को कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक विस्तारित किया है। आयोग के कार्यक्रम में घर-घर जाकर सत्यापन, प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन, दावे और आपत्तियां लेने तथा अंतिम सूची प्रकाशित करने जैसी प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 27 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में किए गए एसआईआर की वैधानिकता को बरकरार रखा और माना कि निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत ऐसी प्रक्रिया संचालित करने का अधिकार है। न्यायालय ने यह भी माना कि प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की रक्षा से जुड़ा वैध उद्देश्य है।

एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर स्वाभाविक रूप से राजनीतिक और सामाजिक बहस पैदा हुई है। लेकिन बेवजह चुनाव आयोग एवं मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर विवाद खड़े किये जाने की स्थितियां विडम्बनापूर्ण हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों की संयुक्त मतदाता सूची में एसआईआर के बाद 10.2 प्रतिशत की कमी हुई और 66,88,636 मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए। इसी प्रक्रिया में आपत्तियां और जांच के बाद 63.16 लाख नाम भी हटाए गए। इन आंकड़ों को केवल एक



राजनीतिक दृष्टि से देखना उचित नहीं होगा। इनमें एक ओर मृत, स्थानांतरित या दोहराए गए नामों को हटाने की प्रशासनिक आवश्यकता दिखाई देती है, तो दूसरी ओर इतनी बड़ी संख्या में नामों में परिवर्तन यह भी बताता है कि मतदाता सूची को नियमित रूप से अद्यतन करते रहना कितना आवश्यक है। यहीं से इस पूरी प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी सामने आती है। यदि किसी संतुलन ही एसआईआर की वास्तविक सफलता के लिए जरूरी है, तो किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से हट जाना भी उतनी ही गंभीर समस्या है। मतदाता सूची को शुद्ध करने और मतदाता अधिकार को सुरक्षित रखने के बीच संतुलन ही एसआईआर की वास्तविक सफलता है। इस दृष्टि से निर्वाचन आयोग का हालिया विशेष अभियान महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर 2026 को आयोग ने एसआईआर पूरी कर चुके राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उन पात्र मतदाताओं को फिर से सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया, जिनके नाम पुनरीक्षण के दौरान छूट गए हों। पहली बार मतदान करने वाले और नए पात्र युवा मतदाताओं के पंजीकरण पर भी जोर दिया गया है।

इस अभियान में बृथ स्तर के अधिकारियों को एसआईआर से पहले की मतदाता सूची और वर्तमान सूची का मिलान कर उन लोगों की पहचान करने को कहा गया है जिनके नाम पहले मौजूद थे लेकिन अंतिम सूची में नहीं हैं। इसके बाद घर-घर जाकर सत्यापन और पात्र पाए जाने पर मौके पर ही फॉर्म-6 प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बृथ स्तर अधिकारी के लिए प्रति सप्ताह 20 से 25 मतदाताओं के सत्यापन और लगभग एक महीने में अभियान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजनीतिक दलों के बृथ स्तर एजेंटों के साथ संबंधित सूचियां साझा करने का निर्देश भी पारदर्शिता की दृष्टि से उल्लेखनीय है। यही वह बिंदु है जहां मतदाता सूची के पुनरीक्षण

विनोद खन्ना ने करियर के शिखर पर छोड़ दिया था बॉलीवुड

अनन्या मिश्रा

आज ही के दिन यानी की 06 अक्तूबर को हिंदी सिनेमा को विनोद खन्ना का जन्म हुआ था। वह उन चुनिंदा सितारों में से एक थे, जिनका सफर निगेटिव रोल से हीरो बनने तक बेहद खास रहा। विनोद खन्ना ने न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता, बल्कि एक अलग पहचान भी बनाई। विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्मों में खलनायक के रूप में की थी।

पेशावर में एक पंजाबी परिवार में 06 अक्तूबर 1946 को विनोद खन्ना का जन्म हुआ था। बच्यवरे के समय उनका परिवार भारत आकर मुंबई में बस गया। विनोद खन्ना को बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद विनोद खन्ना ने एक्टिंग को बतौर अपना

करियर चुना। हालांकि शुरुआत में उनके पिता इसके खिलाफ थे। लेकिन बेटे की मेहनत और लगन देखकर वह भी राजी हो गए। इस तरह से उन्होंने विनोद खन्ना को उनका सपना पूरा करने का मौका दिया।

बता दें कि साल 1968 में विनोद खन्ना को पहली बड़ी सफलता मिली थी। इस दौरान अभिनेता को फिल्म मन का मीत में खलनायक का रोल मिला था। उस दौरान हिंदी फिल्मों निगेटिव रोल या विलेन का रोल निभाना आसान नहीं था। लेकिन विनोद खन्ना ने इसके अपनी ताकत बना लिया। अपने डैशिंग लुक और एक्सप्रेशन के दम पर विनोद खन्ना ने खुद को निगेटिव रोल में भी साबित कर दिखाया।

इसके बाद विनोद खन्ना ने कई फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाई और बतौर



खन्ना को पहली बार मेन रोल में देखा गया। इसके बाद उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ी। यह फिल्म दर्शकों ने इतनी ज्यादा पसंद की कि विनोद खन्ना ने अपना नाम एक हीरो के रूप में पक्का कर लिया।

इसके बाद अभिनेता की कई हिट फिल्में आईं, जैसे- अमर अकबर एंथोनी, कुर्बानी, मेरा गांव मेरा देश और दयावान आदि हैं। इन फिल्मों में विनोद खन्ना ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ विलेन ही नहीं बल्कि बेहतरीन हीरो भी हैं।

विनोद खन्ना ने कभी भी खुद को

को केवल कागजी शुद्धता से आगे बढ़ाकर वास्तविक लोकतांत्रिक समावेशन से जोड़ता है।

यह भी समझना होगा कि मतदाता सूची में सुधार कोई एक बार होने वाला अभियान नहीं हो सकता। शहरों में तेजी से बढ़ता प्रवास, गांवों से शहरों की ओर पलायन, विवाह के बाद निवास परिवर्तन, युवाओं का 18 वर्ष की आयु पूरी करना, मृत्यु और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण लगातार होते रहते हैं। इसलिए आयोग स्वयं मतदाता पंजीकरण को सतत प्रक्रिया मानता है और पात्र नागरिकों के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराता है। वास्तविक चुनौती यह है कि पुनरीक्षण के दौरान हटे हुए प्रत्येक नाम के पीछे एक नागरिक हो सकता है। इसलिए हर हटाए गए नाम को संदेह की दृष्टि से देखना और हर शिकायत को गंभीरता से सुनना आवश्यक है। इसी तरह हर पुराने नाम को केवल इसलिए बनाए रखना भी उचित नहीं होगा कि वह पहले सूची में था। लोकतंत्र में मतदाता सूची का सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए-न पात्र व्यक्ति छूटे और न अपात्र व्यक्ति मतदान व्यवस्था में बना रहे।

लोकतंत्र की मजबूती का अर्थ केवल अधिक मतदान प्रतिशत नहीं है। उसका अर्थ यह भी है कि जो पात्र नागरिक मतदान करना चाहता है, उसे मतदाता सूची में स्थान मिले, जो व्यक्ति मतदान के योग्य नहीं है, उसका नाम नियमपूर्वक हटे, शिकायत करने वाले को सुनवाई मिले और अंतिम निर्णय पारदर्शी प्रक्रिया से हो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिहार एसआईआर की वैधानिकता को स्वीकार किए जाने का अर्थ भी यही है कि मतदाता सूची की शुद्धता का संवैधानिक महत्व है, साथ ही प्रक्रिया में निर्धारित सुरक्षा उपार्यों का पालन आवश्यक है। इसलिए आज आवश्यकता एसआईआर के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने से अधिक महत्वपूर्ण उस प्रक्रिया को इतना पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की है कि किसी पात्र नागरिक को अपने मताधिकार के लिए संघर्ष न करना पड़े। भारतीय लोकतंत्र की शक्ति चुनाव क्राने में भाग लेने, बल्कि हर योग्य नागरिक को चुनाव में भाग लेने का समान अवसर देने में है। मतदाता सूची का शुद्धीकरण लोकतंत्र की सफाई है, लेकिन उस सफाई में कोई निर्दोष नागरिक बाहर न रह जाए, इसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। एसआईआर तभी अपने व्यापक उद्देश्य को पूरा करेगा जब शुद्धता और समावेश, दोनों साथ चलें।

स्टारडम में नहीं फंसने दिया। वह अपनी मेहनत और सादगी से सबका हमेशा दिल जीतते रहे। उन्होंने राजेश खन्ना, सुनील दत्त और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर और अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों में विनोद खन्ना की जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ दर्शकों की फेवरेट रही। साल 1980 के दशक में विनोद खन्ना इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में शामिल थे। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। साल 1982 में विनोद खन्ना अपने आध्यात्मिक गुरु ओशो की शरण में चले गए और फिल्मों से पूरी तरह से दूरी बना ली। फिर करीब 5 साल बाद साल 1987 में फिल्म ईसाफ से विनोद खन्ना ने वापसी की।

आज का इतिहास

- 1723 बेंजामिन फ्रेंकलिन 17 साल की उम्र में फिलाडेल्फिया पहुंचे।
- 1762 ब्रिटिश सैनिकों ने फिलीपींस के मनीला पर कब्ज़ा किया।
- 1862 भारतीय दंड संहिता कानून पारित हुआ और एक जनवरी से लागू हुआ।
- 1919 तांबूलोस्की बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बने।
- 1935 भारत में 32 साल के सबसे लंबे समय तक अंपायरिंग करने वाले जीवन डी घोष का बंगाल में जन्म हुआ।
- 1957 सोवियत संघ ने नोवाया ज़ेमेल्या में परमाणु परीक्षण किया।
- 1972 मेक्सिको में ट्रेन पटरि से उतरने से 208 लोगों की मौत।
- 1980 गुयाना ने संविधान को अंगीकार किया।
- 1981 काहिरा में सैनिक परेड के दौरान एक सैनिक समूह द्वारा मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत की हत्या।
- 1983 पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
- 1987 फिजी एक गणराज्य घोषित हुआ।
- 1994 यूनेस्को ने वर्ष 1995 को संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की।
- 1995 दो स्विस वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सौर व्यवस्था के बाहर गृह की पहली बार पहचान की।
- 1999 संयुक्त राष्ट्र निस्स्त्रीकरण सम्मेलन आस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में प्रारम्भ।
- 2000 इस्पायली पुलिस द्वारा अलअक्सा मस्जिद में जबरन प्रवेश के बाद हिंसा शुरू, यूगोस्लाविया में रक्तहीन जनक्रांति के बीच राष्ट्रपति मिलोसेविच देश छोड़कर भागे, विपक्षी नेता कोस्तुनिका ने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया।
- 2002 नेपाल के नरेश ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह देव ने सत्ता नहीं संभालने की घोषणा की।
- 2004 इस्पायली सैन्य अभियान को रोकने का प्रस्ताव अमेरिका ने वोटो किया। अल्खानोव चेचेन्या में राष्ट्रपति बने।
- 2006 संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में शांति रक्षकों को बल प्रयोग का अधिकार दिया।
- 2007 परवेज मुशर्रफ़ एकतरफ़ा जीत के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित हुए। कोरू में एप्रियन-5 रॉकेट के सहारे आस्ट्रेलियाई-अमेरिकी टेलीविजन उपग्रह का परीक्षण किया गया।
- 2007 बाबा साहेब भोसले – प्रसिद्ध भारतीय वकील, नेता एवं महाराष्ट्र के आठवें मुख्यमंत्री।
- 2008 वैश्विक मंदी के मद्देनज़र भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के नक़द सुरक्षित अनुपात (सीआरआर) में आधा प्रतिशत की कटौती का फैसला किया।

कोविंद समिति से सुप्रीम कोर्ट तक उठे संवैधानिक सवाल

‘विनोद सिंह ‘तकियावाला’

इनदिनों विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एकराष्ट्र-एक चुनाव ,विषय पर चर्चा व चिन्तन पर चहुँ दिशाओं मे हो रही है। लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा अब केवल राजनीतिक बहस का विषय नहीं रह गई है,बल्कि यह मुद्दा शनैः - शनैः देश की संवैधानिक व्यवस्था,संसद की विधायी शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्र भूमिका के बीच संतुलन से जुड़ा एक ज्वलंत प्रश्न बन चुका है। सर्वविदित रहे कि ‘एक राष्ट्र,एक चुनाव’ को लेकर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी।इसके बाद संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद की संयुक्त समिति के विचाराधीन है।इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के साथ संयुक्त संसदीय समिति की प्रस्तावित अनौपचारिक बैठक रद्द होना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रम के रूप में सामने आया है।

सूत्रों के अनुसार संयुक्त संसदीय समिति की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ प्रस्तावित बैठक 6 अक्टूबर को होनी थी। सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव कार्यालय की ओर से संबंधित पक्ष को यह बताया गया कि प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन भविष्य में न्यायिक समीक्षा का विषय बन सकता है।ऐसी स्थिति में वर्तमान न्यायाधीशों द्वारा इस विषय पर प्रशासनिक अथवा अनौपचारिक चर्चा करना उचित या वांछनीय नहीं माना गया।इही कारण रहा कि प्रस्तावित बैठक को आगे नहीं बढ़ाया गया।इस घटनाक्रम को ‘एक राष्ट्र,एक चुनाव’ के विरोध के रूप में देखना उचित नहीं होगा।दरअसल में सवाल किसी चुनाव सुधार का समर्थन या विरोध

नहीं,बल्कि न्यायपालिका की संस्थागत मर्यादा और भविष्य में संभावित न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है।यदि संसद किसी संवैधानिक संशोधन को कानून का रूप देती है और बाद में उसी कानून की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है,तो वर्तमान न्यायाधीशों का उस कानून के निर्माण से पहले उसके विषय में अनौपचारिक चर्चा करना न्यायिक निष्पक्षता के सवाल पैदा कर सकता है। यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की भूमिका को भी समझना आवश्यक है।(‘एक राष्ट्र,एक चुनाव’ पर गठित उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में कोविंद ने इस विषय पर देश के विभिन्न वर्गों,राजनीतिक दलों, विधि विशेषज्ञों और पूर्व न्यायाधीशों से व्यापक विचार- विमर्श किया था।समिति ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी।इस रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में समिति ने 65 बैठकें कीं और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य विधि विशेषज्ञों से भी राय ली।

पूर्व न्यायाधीशों से संवाद और वर्तमान न्यायाधीशों से संभावित कानून पर चर्चा के बीच यही मूल अंतर है।पूर्व न्यायाधीश किसी प्रस्तावित कानून पर स्वतंत्र रूप से अपना कानूनी और संवैधानिक मत रख सकते हैं,क्योंकि वे उस समय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित या संभावित मामले की सुनवाई का हिस्सा नहीं होते।इसके विपरीत वर्तमान न्यायाधीशों के सामने भविष्य में उसी कानून की संवैधानिक समीक्षा का प्रश्न आ सकता है।इसलिए उनसे किसी प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के विषय में अनौपचारिक चर्चा से दूरी बनाए रखना न्यायपालिका की संस्थागत स्वतंत्रता के अनुरूप ही माना जाएगा।।यहाँ दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त संसदीय समिति इससे पहले कई पूर्व प्रधान न्यायाधीशों के विचार सुन चुकी है।पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.एफ़. खेहर,रंजन गोगोई, डी.वाई. चंद्रचूड़ और यू.यू. ललित सहित पूर्व



न्यायिक पदाधिकारियों से समिति ने विचार-विमर्श किया है।इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका के अनुभव और संवैधानिक दृष्टिकोण को इस प्रक्रिया से पूरी तरह अलग नहीं रखा गया है। बल्कि वर्तमान न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों की संवैधानिक भूमिकाओं के अंतर को ध्यान में रखते हुए संवाद का माध्यम अलग रहा है।

‘एक देश, एक चुनाव’ की मूल अवधारणा भी अपने आप में व्यापक है।भारत में पहले भी लोकसभा और अधिकश राज्य विधानसभाओं के चुनाव लंबे समय तक एक साथ होते रहे थे।वर्ष 1951-52 से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव काफी हद तक एक साथ हुए।बाद में कुछ राज्यों की विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने और राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण चुनाव चक्र अलग-अलग होता गया।परिणाम यह हुआ कि आज देश में लगभग हर वर्ष किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते रहते हैं।समर्थकों का तर्क है कि बार-बार होने वाले चुनावों से प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव पड़ता है,सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती करनी पड़ती है,सरकारी संसाधनों का उपयोग होता है और आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्यों की गति प्रभावित हो सकती है।यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों तो चुनावी खर्च कम करने, प्रशासनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और

नीति-निर्माण में निरंतरता लाने में मदद मिल सकती है।इसके विपरीत आलोचकों की चिंता यह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने से राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं।क्षेत्रीय दलों की भूमिका,राज्यों के अधिकार और संघीय ढांचे पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर भी प्रश्न उठते हैं।

यदि किसी राज्य की विधानसभा किसी राजनीतिक कारण से समय से पहले भंग हो जाती है तो उसके चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव चक्र के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और व्यावहारिक प्रश्न है।यही कारण है कि ‘एक राष्ट्र,एक चुनाव’ केवल चुनाव कराने की तारीख बदलने का विषय नहीं है। इसके लिए संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन,लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में समन्वय तथा ऐसी परिस्थितियों के लिए स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक होगी,जब कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले बहुमत खो दे।संयुक्त संसदीय समिति इसी संवैधानिक और विधायी ढांचे का परीक्षण कर रही है।दिसंबर 2024 में संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था।समिति के समक्ष अब विभिन्न पक्षों से विचार- विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों के साथ प्रस्तावित बैठक का रद्द होना यह संकेत देता है कि संसद और न्यायपालिका अपनी-अपनी संवैधानिक सीमाओं और जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं।लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि संसद कानून बनाती है और न्यायपालिका उसकी संवैधानिक कसौटी पर समीक्षा करती है। दोनों संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र अलग हैं,लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोनों की भूमिका एक-दूसरे की पूरक हैं।संसद को कानून बनाने का अधिकार है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को यह देखने का अधिकार है कि

कोई कानून संविधान की मूल भावना और उसके प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं।इस दृष्टि से वर्तमान न्यायाधीशों का प्रस्तावित अनौपचारिक संवाद से अलग रहना किसी ठ्कराव का संकेत नहीं,बल्कि संवैधानिक मर्यादा का उदाहरण माना जा सकता है। न्यायपालिका का यह निर्णय भविष्य में उसके सामने आने वाले संभावित मामले में निष्पक्षता की धारणा को और मजबूत करता है।।‘एक देश, एक चुनाव’ पर अंतिम निर्णय चाहे जिस दिशा में जाए,उसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक स्पष्टता और राज्यों के हितों का संतुलन आवश्यक होगा।नुाव सुधार लोकतंत्र को मजबूत करने का माध्यम होना चाहिए, न कि राजनीतिक मतभेद का नया केंद्र।।भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में किसी भी बड़े चुनावी सुधार की सफलता केवल संसद के भीतर बहुमत से नहीं,बल्कि व्यापक सहमति और जनता के विश्वास से सुनिश्चित होगी।पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने इस बहस को संस्थागत रूप देने का काम किया।अब संयुक्त संसदीय समिति इसे विधायी और संवैधानिक स्तर पर आगे बढ़ा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों का प्रस्तावित बैठक से अलग रहना इस प्रक्रिया में न्यायपालिका की स्वतंत्र भूमिका को रेखांकित करता है।अंततः ‘एक देश, एक चुनाव’ का प्रश्न केवल एक साथ चुनाव कराने या अलग-अलग चुनाव कराने का प्रश्न नहीं है।यह भारत के संघीय ढांचे, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक स्थिरता, चुनावी खर्च, प्रशासनिक दक्षता और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन तलाशने की चुनौती है। यदि इस दिशा में आगे बढ़ना है तो राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ संवैधानिक विवेक भी उतना ही आवश्यक होगा।संसद अपना काम करे और न्यायपालिका अपना दायित्व निभाए, यही स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे मजबूत पहचान है।

भारत और बांग्लादेश के संबंध अब तक पूरी तरह से पटरी पर नहीं

ऐसे वक्त में, जब कई वजहों से ढाका के साथ नई दिल्ली के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं, तब बांग्लादेश के बोगुरा में तुर्किये के सहयोग से झोन फैक्टरी लगाने की उसकी योजना भारत के लिए गंभीर सामरिक चिंता का विषय है। चिंता केवल इस बात की नहीं है कि बांग्लादेश अपनी झोन निर्माण क्षमता बढ़ा रहा है, बल्कि बड़ी रणनीतिक चिंता तेजी से झोन बनाने और उनकी मरम्मत करने वाले बेस का बनना है। दरअसल भारत के बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर (जो पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है) के पास है। इसलिए यहां सैन्य और झोन निर्माण बेस का होना भारत के इस मुख्य चोकपॉइंट (अहम और संकरे रास्ते) के लिए सामरिक जोखिम पैदा करता है। इस प्रस्तावित फैक्टरी के पास एक नए एयरफ़ोर्स बेस और अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे को उन्नत करने की भी योजना है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में सैन्य गतिविधियों के लिए एक बड़े रणनीतिक हब के रूप में किया जा सकता है। तुर्किये भारत के पारंपरिक रणनीतिक साझेदारों के दायरे से बाहर है और भारत- तुर्किये के रिश्ते जिससे से ही तनावपूर्ण भी हैं। यह वही देश है, पहिले ऑपरेशन सैल्टक के समय पाकिस्तान की मदद की थी। यही नहीं, पाकिस्तान पहले से ही भारत की पश्चिमी सीमा पर तुर्किये के झोन का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में पूर्व में तुर्किये के सहयोग से बनने वाली बांग्लादेश की बोगुरा झोन फैक्टरी भारत के हवाई-रक्षा संसाधनों पर दबाव डाल सकती है। बांग्लादेश पहले से ही तुर्किये से झोन खरीदता है, लेकिन बोगुरा में झोन फैक्टरी की



योजना बांग्लादेश के एक बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है। जनवरी में, बांग्लादेश एयर फ़ोर्स ने बांग्लादेश के अंदर झोन बनाने और उसे असेंबल करने का प्लांट लगाने के लिए चीन की कंपनी चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल (सीईटीसी) के साथ भी एक समझौता किया। चीन और तुर्किये के साथ समझौतों से उसे इंजीनियर, असेंबली लाइन, मेंटेनेंस की स्किल और देश में ही बिना पायलट वाले एयरक्राफ्ट बनाने का अनुभव मिल सकता है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में तख्तापलट और नई सरकार के बनने के बाद यहां पाकिस्तान, तुर्किये और चीन का रक्षा व कूटनीतिक दखल तेजी से बढ़ा है। क्षेत्रीय राजनीति में इसे भारत के खिलाफ माहौल बनाने और सामरिक दबाव बढ़ाने के एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। भारत के लिए असली रणनीतिक सवाल यह नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश आज कितनी क्षमता के झोन बना सकता है, बल्कि यह होना चाहिए कि वह अगले पांच या दस वर्षों में किस स्तर की क्षमता हासिल कर सकता है। बदलते क्षेत्रीय समीकरणों के बीच इसी दीर्घकालिक दृष्टि के साथ नई दिल्ली को अपनी पूर्वी सुरक्षा नीति तैयार करनी होगी।

यूपी में धनराज नाथवानी से क्या अखिलेश एक तीर दो निशाना साध रहे हैं ?

सौरभ वार्षणेय

समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए धनराज परिमल नाथवानी को उम्मीदवार बनाकर पूरे देश में एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। सपा पार्टी ने वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव के साथ नाथवानी का नाम घोषित किया। रामगोपाल यादव सपा के पुराने और स्थापित राजनीतिक चेहरे हैं, जबकि धनराज नाथवानी की पहचान मुख्यतः व्यावसायिक घराने से जुड़ी रही है। यही अंतर इस फैसले को अलग बनाता है। वहीं राजनीतिक इसे योगी के लिए भी कुछ संकेत बता रहे हैं।

ज्ञात रहे कि धनराज नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उनका सार्वजनिक जीवन पारंपरिक समाजवादी राजनीति से अलग रहा है। इससे भी अधिक दिलचस्प तथ्य यह है कि उनके पिता परिमल नाथवानी स्वयं राज्यसभा के सदस्य हैं और जून 2026 में झारखंड से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फिर राज्यसभा पहुंचे हैं। पिता एक खेमे के समर्थन से राज्यसभा में हों और पुत्र सपा के उम्मीदवार बनें, तो सवाल उठना लाजिमी है ?

सवाल है कि क्या अखिलेश यादव का यह फैसला केवल राजनीतिक रणनीति है या इसके पीछे सत्ता के विभिन्न केंद्रों के बीच कोई संवाद भी है? क्या इसे केंद्र सरकार से समझौते का संकेत माना जाए? उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर ऐसी किसी गुप्त राजनीतिक डील का प्रमाण सामने नहीं आया है। इसलिए इसे समझौते का परिणाम बताना अभी अटकल होगी। लेकिन राजनीति में प्रतीक महत्वपूर्ण होते हैं और नाथवानी की उम्मीदवारी ऐसा ही प्रतीक बन गई है।

नाथवानी परिवार की पृष्ठभूमि इस चर्चा को महत्वपूर्ण बनाती है। परिमल नाथवानी लंबे समय से रिलायंस समूह से जुड़े रहे हैं और अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों में राज्यसभा तक पहुंचे हैं। वर्तमान में उनका रास में प्रवेश राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समर्थन से हुआ। दूसरी ओर उनके पुत्र को अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुना है। यह घटनाक्रम बताता है कि राजनीतिक संबंध हमेशा पारिवारिक या कारोबारी संबंधों के साथ नहीं चलते। ऐसे उदाहरण पहले भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां इसे महत्व देती हैं।



यहीं से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस फैसले के संभावित राजनीतिक संकेत को समझने की कोशिश की जा सकती है। इसे समझौते का प्रमाण मानना उचित नहीं, लेकिन यह जरूर देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अपनी पहुंच को पारंपरिक सामाजिक आधार से आगे बढ़ाना चाहती है। उद्योग, निवेश, रोजगार, कारोबारी जगत और राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली समूहों से संवाद बढ़ाना किसी भी दल की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। यदि सपा आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय की राजनीति से जोड़ती है, तो नाथवानी की उम्मीदवारी उस दिशा का संकेत हो सकती है।

यहां अखिलेश की तुलना उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से करना स्वाभाविक है। मुलायम सिंह यादव वैचारिक पहचान बनाए रखते हुए अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक समूहों से संवाद करते थे। उन्होंने परंपरागत समर्थक वर्ग से आगे व्यापक राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश की। विभिन्न सामाजिक समूहों और दलों से संवाद उनकी राजनीति की पहचान रहा। सवाल यह है कि क्या अखिलेश भी उसी व्यावहारिक शैली की ओर लौट रहे हैं? अखिलेश की राजनीति में पिछले वर्षों में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए सामाजिक समीकरण प्रमुख रहा है। ऐसे में रिलायंस से जुड़े को राज्यसभा भेजना अलग संदेश देता है। विपक्षी दलों ने इसी अंतर को मुद्दा बनाया है। बसपा प्रमुख मायावती ने नाथवानी और रामगोपाल यादव के चयन को सपा के पीडीए दावे से जोड़कर सवाल उठाए। सपा का तर्क है कि समाजवाद का उद्देश्य रोजगार, विकास और समृद्धि है तथा इसके लिए उद्योग और निवेश आवश्यक हैं।

यही बहस नाथवानी की उम्मीदवारी का वास्तविक राजनीतिक अर्थ हो सकती है। क्या सपा सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास और निवेश को भी केंद्रीय संदेश

मृत्युंजय दीक्षित

वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी जहां एक ओर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए चुनाव आयोग व देश की अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर हमलावर है वहीं दूसरी ओर उसके तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं का विभाजन करके कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाकर राजनैतिक माहौल को गर्म कर दिया है। दक्षिण का राज्य तेलंगाना कांग्रेस के शासन में आर्थिक तंगी व भ्रष्टाचार से गुजर रहा है। अपनी प्रशासनिक नाकामियों तथा चुनावी दादों को पूरा करने में नाकाम रहने व मुस्लिम तृष्िकरण को छुपाने के लिए रेवंत रेड्डी ने प्रभु श्रीराम को उत्तर और भगवान शिव को दक्षिण का देवता बताकर एक नयी विभाजक रेखा खींचने का असफल प्रयास किया है। उत्तर भारत में अपने अस्तित्व का संघर्ष करती कांग्रेस अब विभाजनकारी मानसिकता के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गयी लगती है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इससे पूर्व भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि मुस्लिम ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही मुस्लिम है। रेवंत रेड्डी का कहना है कि भगवान राम अमीरों के देवता हैं और भगवान शिव गरीबों के देवता हैं। वे स्वयं को भगवान शिव का भक्त बताते हुए कहते हैं कि भाजपा ने भगवान राम को चोरी कर लिया है। रेवंत रेड्डी का कहना है



भाजपा के लोग हर हर महादेव तक नहीं बोलते। वह एक बार हिंदुओं के 33 करोड़ देवताओं पर भी विकृत बयानबाजी कर चुके हैं। दिमागी नक्सली नेताओं का यही लक्ष्य रहता है किसी न किसी प्रकार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाए। विगत सितम्बर में हुए गणेशोत्सव आयोजन के दौरान तेलंगाना में कई जगह से गणेशेत्सवों के आयोजन पर बाधाओं के समाचार आ रहे थे।

कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कारिडोर का विरोध किया। जानवापी में मिले शिवलिंग को फव्वारा बताने में सबसे पहले कांग्रेस ही मैदान में उतर पड़ी थी। रेवंत रेड्डी संभवतः यह बात भूल गए कि भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समाज की रक्षा के लिए विष को भी अपने गले में ही धारण कर लिया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भगवान श्रीराम का चरित्र पढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि भगवान श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी कांग्रेस ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की रणनीति के तहत

ही विगत 76 वर्षों में हिंदू समाज को जाति, पंथ, संप्रदाय, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटने की पूरी कोशिश की है और वह लगातार जारी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने बयान के माध्यम से अर्थां बनाम द्रविड का विभाजन करते हुए यह भी कहाकि हम द्रविड़ हैं और हम भगवान शिव की आराधना करते हैं जबकि आर्य प्रभु श्रीराम को मानते हैं।

रेवंत रेड्डी का कहना है कि बीजेपी के मंचों से जयश्रीराम का नारा सुनाई देता है जबकि हर हर महादेव का उद्घोष नहीं किया जाता। रेड्डी ने कहा कि मोदीजी हर हर महादेव क्यों नहीं कहते? रेवंत रेड्डी का बयान झूठ का पुलिंदा भर है। रेवंत रेड्डी को यह नहीं पता कि उत्तर भारत में केदारनाथ, विश्वनाथ और महाकाल जैसे ज्योतिर्लिंग हैं, उत्तर भारत में ही कौण्ड्य यात्रा होती है और श्रावण माह महादेव को ही समर्पित रहता है।

कांग्रेस को तो भगवान शिव के मंदिरों के विकास से भी चिढ़ रही है। गुजरात के पवित्र सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार रोकने और तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर न जाने देने का भरसक प्रयास स्वयं नेहरु जी ने किया था। सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिभाग पर भी कांग्रेस ने नफरत भरा बयान दिया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बने भव्य महाकाल कांिरडोर का विरोध भी कांग्रेस नेताओं ने ही किया था।

आज दक्षिण भारत के जो कांग्रेसी नेता

अपने आपको शिवभक्त बता रहे हैं वह ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के उद्धार के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? कांग्रेस के शासनकाल में भगवान शिव के मंदिरों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक बार काशी विश्वनाथ धाम और सोमनाथ मंदिर में जाकर शिव की आराधना करते हैं जबकि आर्य प्रभु श्रीराम को मानते हैं।

यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस के नेता कभी अन्य धर्मों के प्रति इस प्रकार के बयान क्यों नहीं देते? यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। गांधी परिवार व विपक्ष को अयोध्या का भव्य राम मंदिर व काशी विश्वनाथ धाम सहित अन्य मंदिरों का विकास अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए अब उसने यह नया नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी व बीजेपी के लोग हर- हर महादेव नहीं बोलते।

वास्तविकता ये है देश की जनता कांग्रेस को इस फूट डालो-राज करो की नीति अच्छी तरह से समझ चुकी है। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार सिमट रही है।

सार्क ने 12 वर्षों में कोई शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया

मनीष तिवारी

13 सितम्बर को जैसे ही अंतिम ब्रिक्स काफिला भारत मंडपम से निकला, जिसके 2 सप्ताह पहले एस.सी.ओ. शिखर सम्मेलन और आगे जी20 था, तो किसी को एक गुस्ताख सवाल पूछने के लिए माफ किया जा सकता है-भारत आखिरी बार अपने सभी 7 दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ एक मेज पर कब बैठा था? वह 27 नवम्बर, 2014 को काठमांडू में था। उसके बाद से सब कुछ खाली कुर्सी का ही एक इतिहास रहा है। विडंबना तीखी है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स नेताओं से कहा कि ग्लोबल साऊथ दुनिया के संकटों की अग्रिम पंक्ति में और उसके फैसलों की पिछली पंक्ति में बैठता है और हमें इस ‘विशेषाधिकार के गिरामिड’ को ‘सांझेदारी के मंच’ में बदलना चाहिए। दक्षिण एशिया, जो मानवता का एक चौथाई हिस्सा है, उसकी कोई पंक्ति ही नहीं है। प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. के आधार पर पीटरसन इंस्टीच्यूट फॉर इंटरनैशनल इकोनॉमिक्स का एक अनुमान बताता है, ‘ग्लोबल साऊथ दुनिया की 85 प्रतिशत आबादी और वैश्विक जी.डी.पी. के लगभग 39 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है’। सार्क ने 12 वर्षों में कोई शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया और इसके विदेश मंत्री औपचारिक रूप से आखिरी बार मार्च 2016 में मिले थे। दूर के ढोल सुहावने लाते हैं। पड़ोस में ढोल एक दशक से खामोसी है। सार्क किसी अन्य के विचार से पहले बंगलादेश का विचार था और इसके 1985 के चार्टर ने इसे कागज पर पृथ्वी का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्रीय समूह बना दिया। कागज पर ही इसका अधिकांश हिस्सा सीमित रहा है। अनुच्छेद ड्रइडू नेताओं को वर्ष में कम से कम एक बार मिलने के लिए प्रतिबद्ध करता है। अनुच्छेद ड्र प्रत्येक स्तर पर सर्वसम्मति की मांग करता है और ‘द्विपक्षीय और विवादाम्यद मुद्दों’ को बाहर रखता है। सार्क की आबादी का लगभग तीन-चौथाई और उसके उत्पादन का 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा भारत का है। सर्वसम्मति, जो प्रवेश का मूल्य था, ने सभी को वीटो दे दिया। यह मंच

पंगु होने से बहुत पहले ही कमजोर हो चुका था- इसके 18 में से 11 शिखर सम्मेलन स्थगित किए गए थे, वे सभी 18 सितम्बर, 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी में 12वीं इफेंड्री ब्रिगेड के प्रशासनिक बेस पर हुए आतंकी हमले से पहले के थे। श्रीलंका ने 1980 के दशक के उत्तरार्ध में तब तक मेजबानी करने से इंकार कर दिया, जब तक कि भारतीय शांति सेना (आई.पी.के.एफ.) वापस नहीं हट गई, मालदीव और भूटान ने बुनियादी ढांचे, वित्तीय और राजनीतिक बाधाओं के कारण इसे स्थगित किया और पाकिस्तान, बंगलादेश तथा नेपाल में घरेलू अस्थिरता के कारण आगे और व्यवधान उत्पन्न हुए। विदेश मंत्री 2021 तक महासभा के इतर अनौपचारिक रूप से मिलते रहे, जब काबुल की ओर से कौन बोलता है, इस सवाल ने इसे भी समाप्त कर दिया। नेपाल 2014 से अध्यक्ष पद पर बना हुआ है। समितियां संयुक्त सचिव स्तर पर मिलती हैं और बकाए का भुगतान किया जाता है। नई दिल्ली ने वही किया जो बड़ी शक्तियां करती हैं-उसमें मंच के इर्द- गिर्द निर्माण किया। उरी के एक महीने के भीतर, भारत ने गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ- साथ बिस्मटेक आऊटरीच शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। बंगाल की खाड़ी के इस समूह में सार्क के 8 में से 5 सदस्य हैं और पाकिस्तान नहीं है। यह काबुल, माले या सिंधु तक नहीं पहुंच सकता। पड़ोस ने विनम्रता से इंतजार करना बंद कर दिया है। बंगलादेश, जो इस मंच का रचयिता था, इसका सबसे मुखर शोक मनाने वाला रहा है। मुहम्मद यूसुफ ने दिसम्बर में कहा था कि वह सार्क की बैठक के लिए ‘भले ही केवल 5 मिनट के लिए’ तैयार हो जाते। तारिक रहमान की निर्वाचित सरकार पुनरुद्धार को एक विदेश नीति का उद्देश्य मानती है और कहती है कि ढाका को सार्क और बिस्मटेक के बीच चयन करने की आवश्यकता नहीं है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजुजू ने 2 बार पुनरुद्धार का आह्वान किया और माले को मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत किया है।



सर्व पितृ अमावस्या पर कब, कितने और कहां जलाएं दीये?

अश्विन माह की अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है।

अश्विन माह की अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सर्व पितृ अमावस्या का हिन्दू धर्म में बहुत महत्व है। ज्योतिष एवं धर्म शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन किया गया पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म पितरों को भगवान विष्णु के धाम वैकुण्ठ में स्थान दिलाता है। इसके अलावा, सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दीया जलाना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसे में ज्योतिषाचार्य से आइये जानते हैं कि आखिर सर्व पितृ अमावस्या के दिन कितने दीये जलाने चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि किस दिशा या किन स्थानों पर दीये जलाना शुभ है एवं किस समय जलाने चाहिए।

सर्व पितृ अमावस्या पर कितने दीये जलाने चाहिए?

शास्त्रों में वर्णित जानकारी के अनुसार, सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त 11 और 1 चौमुखी दीया भगवान विष्णु के निमित्त जलाना चाहिए।

सर्व पितृ अमावस्या पर कहां दीये जलाने चाहिए?

पीपल के पेड़, घर की दक्षिण दिशा, घर का मुख्य द्वार, चौराहा, घर की छत और पवित्र नदी के तट पर सर्व पितृ अमावस्या के दिन दीये जलाने चाहिए।

सर्व पितृ अमावस्या पर किस समय दीये जलाने चाहिए?

सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दीया दोपहर के समय जलाएं। वहीं, इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त दीया ब्रह्म मुहूर्त में जलाना शुभ है।

सर्व पितृ अमावस्या पर कौन सा दीया जलाना चाहिए?

पितरों के लिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन सरसों के तेल में तिल मिलाकर दीया जलाएं। भगवान विष्णु के समक्ष घी का चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें।

सर्व पितृ अमावस्या पर दीया जलाने के क्या लाभ हैं?

इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु के समक्ष दीया जलाने से पितृ दोष में राहत मिलती है।



श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व है

पंचांग के हिसाब से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्व पितृ अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन सभी प्रकार के श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि पितृ दोष होने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर्व पितृ अमावस्या पर किए गए पिंडदान से पितृ दोष का निवारण होता है। सर्व पितृ अमावस्या का दिन सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। पिंडदान में तिल, जल और कुश आदि का उपयोग किया जाता है। श्राद्ध में अपने पूर्वजों के नाम पर भोजन बनाकर ब्राह्मणों को दान किया जाता है। इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप अन्न, वस्त्र, धन आदि दान कर सकते हैं। इस दिन मंदिर जाकर भगवान विष्णु और पितरों का पूजन किया जाता है। अब ऐसे में इस साल सर्व पितृ अमावस्या कब है, पितरों का श्राद्ध किस समय करना शुभ माना जाता है। साथ ही इस अमावस्या तिथि का महत्व क्या है। शास्त्रानुसार ब्राह्मणों के मुख द्वारा ही देवता 'हव्य' एवं पितर 'कव्य' ग्रहण करते हैं। लेकिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन के भी विशेष नियम होते हैं। श्राद्ध भोक्ता ब्राह्मणों को इनका अनुपालन करना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं कि शास्त्रानुसार श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने वाले ब्राह्मणों को किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

- श्राद्ध भोज करने वाले ब्राह्मण को संध्या करना आवश्यक है। श्राद्ध भोज करने वाला ब्राह्मण श्रौत्रिय होना चाहिए जो गायत्री का नित्य जप करता हो।
- श्राद्ध भोज करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन करते समय मौन रहकर भोजन करना चाहिए, आवश्यकतानुसार केवल हाथ का संकेत करना चाहिए।
- श्राद्ध भोज करते समय ब्राह्मण को भोजन की निंदा या प्रशंसा नहीं करनी चाहिए।
- श्राद्ध भोज करने वाले ब्राह्मण से भोजन के विषय में अर्थात 'कैसा है' यह प्रश्न नहीं करना चाहिए।
- श्राद्ध भोक्ता ब्राह्मण को पुनर्भोजन अर्थात एक ही दिन दो या तीन स्थानों पर श्राद्ध भोज नहीं करना चाहिए।
- श्राद्ध भोक्ता ब्राह्मण को श्राद्ध भोज वाले दिन दान नहीं देना चाहिए।
- श्राद्ध भोक्ता ब्राह्मण को श्राद्ध भोज वाले दिन मैथुन नहीं करना चाहिए।
- श्राद्ध भोक्ता ब्राह्मण को केवल चांदी, कांसे या पलाश के पत्तों पर परोसा गया भोजन ही करना चाहिए। श्राद्ध में लोहे व मिट्टी के पात्रों का सर्वथा निषेध बताया गया है।

सर्व पितृ अमावस्या का महत्व

सर्व पितृ अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्ति होती है। साथ ही पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही सुख-शांति और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है।



हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महीना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान पितरों की पूजा करने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष में विधिवत रूप से श्राद्ध कर्म, तर्पण और और पिंडदान करने से लाभ हो सकता है। आपको बता दें, पितृपक्ष में कई बार जातक नियमित रूप श्राद्ध नहीं कर पाते हैं। इसलिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन करने से व्यक्ति को उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। पितृपक्ष में कई तरह के पिंड बनाएं जाते हैं। जिससे व्यक्ति को लाभ हो सकता है। अब ऐसे में पितृपक्ष में पितरों को खीर का पिंड देने का महत्व क्या है।

पितरों को खीर का पिंड देने का महत्व क्या है?

पितरों को खीर का पिंड देना हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, विशेषकर पितृ पक्ष के दौरान। यह माना जाता है कि इस अनुष्ठान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। खीर को एक पवित्र भोजन माना जाता है। इसे देवताओं को भी अर्पित किया जाता है। पितरों को खीर देने से यह विश्वास होता है कि वे इस पवित्र भोजन का आनंद लेते हैं। खीर में चावल और

सनातन धर्म में सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दौरान पितरों की पूजा विधिवत रूप से करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा घर-परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन अगर विधिवत रूप से दान-पुण्य किया जाए, तो पूजा का सीधा फल पूर्वजों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है।

पितृपक्ष में पितरों को खीर का पिंड देने का क्या है महत्व?

दूध दोनों होते हैं। चावल समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है, जबकि दूध शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। इसलिए, खीर को शक्ति और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें, खीर मीठा होता है और माना जाता है कि यह पितरों को तुष्ट करता है। इतना ही नहीं, खीर को परिवार के सदस्यों के बीच आत्मिक संबंध को मजबूत करने का भी प्रतीक माना जाता है।

खीर के पिंड से मिलता है पितृ ऋण से छुटकारा

हिंदू धर्म में पितृ ऋण का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि माता-पिता ने हमें जीवन दिया है और हमें पालन-पोषण किया है, इसलिए हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। पितरों को खीर का पिंड देकर हम इस ऋण का कुछ अंश चुकाते हैं। पितरों को खुश करके हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। पितरों को खीर का पिंड देकर हम उनकी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद करते हैं।



सर्व पितृ अमावस्या के दिन करें इन चीजों का दान, पितरों का मिलेगा आशीर्वाद

हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की अमावस्या तिथि को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पितरों के लिए विधिवत रूप से तर्पण किया जाता है। ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो सके।

ऐसे में सर्व पितृ अमावस्या के दिन किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है।

सर्व पितृ अमावस्या के दिन करें तिल का दान

हिंदू धर्म में तिल को पितरों का सबसे प्रिय अन्न माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तिल का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिल का दान पितृ दोष को दूर करने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। तिल का दान करने से घर में शांति और समृद्धि आती है। यह माना जाता है कि तिल का दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सफलता मिलती है।

सर्व पितृ अमावस्या के दिन करें पिंडदान

सर्व पितृ अमावस्या के दिन पिंडदान करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि पिंडदान करने से व्यक्ति को सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पिंडदान करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि आप अपने पितरों का ध्यान जरूर करें। ऐसा करने से जातकों को पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती है।

सर्व पितृ अमावस्या के दिन करें वस्त्र दान

सर्व पितृ अमावस्या के दिन वस्त्र का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस अमावस्या तिथि के दिन जो व्यक्ति वस्त्र दान करता है। उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही दरिद्रता से भी छुटकारा मिल जाता है। बता दें, वस्त्र दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और वे अपने वंश पर आशीर्वाद बरसाते हैं।



आखिर अब क्यों नहीं देवी देवता आकर दिखाते हैं ऐसे चमत्कार

कहां गए वह देवी-देवता

पांच हजार साल पहले का कोई आदमी आज धरती पर आ जाए तो उसे आश्चर्य होगा कि यक्ष, देव, अशरीरी आत्माएं और किन्नर आदि कहां गए, यह भी कि इच्छा करते ही मनपसंद भोजन और नसन भूषण क्यों नहीं मिल रहे।

वे देवी देवता कहां गए जो बुलाने पर चले आते और इच्छित सुविधाओं को तत्काल रच देते थे। यह उल्लेख आज की दुनिया को सौ डेढ़ सौ साल पहले की दुनिया से जुलान करने वालों को भी इरान कर सकते हैं।

हिमालय के इन भागों में दिखते हैं चमत्कार

उनके हिसाब से आज की दुनिया पिछली सदी से बहुत आगे है पर ईशा फाउंडेशन

कोयंबटूर (तमिलनाडु) की प्रयोगशाला के नतीजों को देखें तो मानना होगा कि पांच हजार साल पहले की दुनिया के बारे में पुराणों और योगशास्त्रों में जो लिखा है, वह अधिकांश सही साबित हो रहा है।

फाउंडेशन के संस्थापक और योग की सचाइयों को दुनिया में पहुंचाने के मिशन में लगे सदस्रु जगमी वासुदेव का कहना है कि ऋग्वेद काल में तारों की रीर करने और वहां से लोगों के पृथ्वी पर आने के वृत्तांत सुनते आए हैं।

आकाश में रह कर धरती के लोगों के लिए सुख सुविधा रचने वालों के बारे में दुनियाभर की पुरानी किताबों के वर्णन इस बात की गवाही देते हैं। हिमालय के ध्रुव प्रदेश में तमाम ऐसी चीजें होते हुए आज भी देखी जा सकती हैं जो असंभव लगती हैं।

शास्त्रों और पुराणों में बताए

चमत्कार की सच्चाई

वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, तो हर जगह लगभग एक जैसी कहानियां न बनी होती। बाइबल में खारकर यूनानी संस्कृति में भी ऐसे ही उल्लेख आए हैं। यहां तक कि नाम भी एक जैसे लगते हैं।

सुमेरियन संस्कृति, मेसोपोटामिया की संस्कृति, अरब की कुछ खास संस्कृतियों, अफ्रीका के उत्तरी भागों में और दक्षिण अमेरिका में भी यही बातें सुनने व पढ़ने को मिलती हैं। हजारों सालों तक इन महाद्वीपों के बीच कोई संपर्क ही नहीं रहा है। इसके बावजूद इन जगहों पर एक जैसे शब्दों और मुहावरों का उपयोग मिलता है।

हिमालय को योगियों और सिद्धों का तीर्थ बताते हुए तिब्बती लामा जेन सामी का कहना है कि साधना की उच्च स्थिति में पहुंचे लोगों को आज भी इस तरह के अलौकिक अनुभव होते हैं।

सार यह है कि दुनिया हमेशा उसके रचयिता की तरह पूर्ण विकसित रही है। कभी कोई पक्ष सामने आता है, कभी कोई। लेकिन योग के सहारे उसे समग्र रूप में देखा और समझा जा सकता है।

वास्तु शास्त्र

पर लोग अशुभ जीव मानते हैं। कहते हैं घर में अक्सर बिल्ली का आने का मतलब है कोई अपशकुन होने वाला है। बिल्ली का घर में मल त्याग करना अनहोनी का संकेत माना जाता है।



का नाम मानकी निको है। चीन और जापान में इस बिल्ली को शुभ का प्रतीक माना जाता है। यह बिल्ली धन को आकर्षित करती है इसलिए इसे मनी कैट भी कहा जाता है।

धन चाहिए तो आपको ऐसी बिल्ली रखनी चाहिए मनी कैट बाजार में कई रंग के मिलते हैं। रंग के अनुसार इनका परिणाम भी अलग-अलग प्राप्त होता है। जैसे

भरपूर प्यार के साथ धन भी मिलेगा, अगर घर में होगी यह बिल्ली

बिल्ली को आमतौर

पर लोग अशुभ जीव मानते हैं। कहते हैं घर में अक्सर बिल्ली का आने का मतलब है कोई अपशकुन होने वाला है। बिल्ली का घर में मल त्याग करना अनहोनी का संकेत माना जाता है।

लेकिन एक बिल्ली ऐसी है जो घर में रहे तो अपशकुन नहीं बल्कि शागुन ही शागुन होता है। यह बिल्ली धन को आकर्षित करती है साथ ही आपके जीवन में प्यार भरपूर लाती है। क्या है इस बिल्ली का नाम

आपके जीवन में खुशियां और धन लाने वाली यह बिल्ली

अगर आप धन की चाहत रखते हैं तो घर या व्यापारिक प्रतिष्ठान पीले रंग की बिल्ली रखें। धन प्राप्ति के लिए आप चाहें तो नीले रंग की बिल्ली भी रख सकते हैं।

प्यार में भाग्य का साथ पाने के लिए प्यार में भाग्य आपका साथ दे इसके लिए आप लाल रंग की बिल्ली घर में रख सकते हैं। हरे रंग की बिल्ली आपको हर चीज में भाग्य का साथ दिलाती है।

लेकिन बिल्ली से लाभ पाने के लिए कुछ नियम भी हैं। हरे रंग की बिल्ली उत्तर पूर्व में रखें। लाल रंग की बिल्ली को दक्षिण पश्चिम दिशा में। पीले और नीले रंग की बिल्ली दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व में रखें।



राहुल गांधी ने एमपी के सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों और राज्य में शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों के चल रहे आंदोलन के मुद्दे पर बात की है। 29 सितंबर को लिखे अपने पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि इंदौर में स्कूल की गूंज कार्यक्रम के दौरान शिक्षक उम्मीदवारों ने क्लास-2 और क्लास-3 के शिक्षक पदों पर भर्ती बढ़ाने का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों के एक लाख से ज्यादा पद खाली हैं, जिसका सीधा असर राज्य में बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षक भर्ती 2025 प्रक्रिया के तहत क्लास-3 के 13,089 और क्लास-2 के 10,800 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है, और उम्मीदवार इन खाली पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को उन फैसलों के रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया, जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार के अधिकारों के इस्तेमाल पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं में चुनौती दी गई है। इन फैसलों में फॉर्म 6 में किए गए विवादित बदलाव भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि वह यह जांचना चाहता है कि क्या ये फैसले अकेले ज्ञानेंद्र कुमार ने लिए थे या चुनाव आयोग ने सर्वसम्मति से या बहुमत से इन्हें मंजूरी दी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा, जब रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, तो हम देखना चाहेंगे कि फॉर्म 6 में किसने बदलाव किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अध्यक्षता वाली बेंच तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में सीईसी (मुख्य चुनाव आयुक्त) द्वारा एसआईआर प्रक्रिया पर लिए गए उन फैसलों को चुनौती दी गई थी, जो कथित तौर पर अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा तरीके से लिए गए थे।

सौरव दास और दिपके को गिरफ्तार करने की तैयारी

नईदिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास ने आरोप लगाया है कि सरकार उन्हें और पार्टी के अन्य नेताओं को 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले पार्टी के बड़े विरोध प्रदर्शन से पहले गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। दास द्वारा बताए गए नेताओं में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका शामिल हैं। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए बुलाया गया है, जो मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) से जुड़ा है। रविवार देर रात एक पोस्ट में दास ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि ऐसे तानाशाही भरे कदमों से तय प्रदर्शन को रोका जा सकता है, तो वह गलतफहमी में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मुझे, अभिजीत, आशुतोष, रत्ना और कॉकरोच जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। अगर सरकार को लगता है कि ऐसे तानाशाही भरे कदम काम आएंगे, तो वह गलत है!

दिग्विजय सिंह के बचाव में उतरे प्रियांक खड़गे

बेंगलुरु। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर तीखा हमला करते हुए संगठन को धर्म की आड़ में चल रही बिना रजिस्ट्रेशन वाली मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट बताया। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के गृह मंत्री ने आरोप लगाया आरएसएस असल में बिना रजिस्ट्रेशन वाली मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट के अलावा कुछ नहीं है, जो धर्म के नाम पर सभी तरीह की गैर-कानूनी गतिविधियां कर रही है। यह बयान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के उस आरोप के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय विमर्श पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने हिंदुत्व के बारे में लगातार बयानबाजी करके कब्जा कर लिया है, जिससे हिंदुओं और अन्य धर्मों के बीच दरार पैदा हो रही है; इस बयान की साधु-संतों और भाजपा नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी। सिंह का बचाव करते हुए, खड़गे ने कांग्रेस नेता को आस्था का पक्का अनुयायी बताया।

राज्यसभा टिकट मिलने के बाद कोयल मल्लिक भाजपा में शामिल

कोलकाता। बंगाली फिल्म अभिनेत्री रुक्मिणी मल्लिक सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गईं। भाजपा ने एक दिन पहले रुक्मिणी मल्लिक को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। रुक्मिणी कोयल मल्लिक के नाम से लोकप्रिय हैं। दिगगज बंगाली फिल्म अभिनेता रंजीत मल्लिक की बेटी कोयल मल्लिक इससे पहले तुणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। उन्होंने छह अप्रैल से 16 जुलाई तक थोड़े समय के लिए राज्यसभा सदस्य के रूप में काम किया था। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कोयल मल्लिक का भाजपा में स्वागत करते हुए पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई की महासचिव शशि अनिनहोत्री ने कहा कि अभिनेत्री सोमवार को राज्यसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मल्लिक ने कहा, “संसद के उच्च सदन की सदस्य बनना और लोगों के कल्याण के लिए काम करने का अवसर मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है।”

सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर बोले संबित पात्रा

देश में स्वतंत्र रूप से काम कर रहीं संस्थाएं : भाजपा

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग से संबंधित याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोग और केंद्र को नोटिस जारी किया जाना इस बात का ‘सबूत’ है कि देश में सभी संस्थाएं ‘स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं’ और ‘डर तथा तानाशाही’ का माहौल नहीं है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस घटनाक्रम के बारे में पूछे जाने पर कहा, “देश बहुत लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। हर कोई अपने मन की बात कह रहा है।



शासन’ में चल रहा है और आज देश में तानाशाही या निरंकुशता है।” भाजपा सांसद ने कहा कि इन दावों के विपरीत देश में डर का माहौल बिल्कुल नहीं है। पात्रा ने कहा, “लोकतंत्र का माहौल है। इसलिए जो लोग दावा करते थे कि देश में डर का माहौल है, मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं है। पात्रा ने कहा कि ‘इस पूरे मामले’ को उच्चतम न्यायालय में ले जाना गूरा और शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किए, यह भी इस बात का उदाहरण है कि लोकतंत्र काम कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को जारी किया नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उन याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिनमें आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग ने दोनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बिना कई फैसले लिए। न्यायालय ने कहा कि जो भी फैसला कानून के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने याचिका पर अंतिम फैसला आने तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को कोई भी फैसला लेने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल्ल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि वह उस कानूनी प्रावधान की भी जांच कर सकती है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद छोड़ने के बाद भी कानूनी संरक्षण देता है। पीठ ने कहा, “ हम सभी फैसलों की जांच करेंगे।

पंजाब में सियासी भूचाल! आप सरकार पर सबसे बड़ा संकट!

सीएम मान के दफ्तर तक पहुंची आंच हार्ड कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के दफ्तर और करीबियों से जुड़े भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच केन्द्रिय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को लिखे गए पत्रों और राज्य पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद आया है। ईडी ने सीनियर पुलिस अधिकारी को तीन पत्र लिखकर पंजाब में सरकारी ट्रॉसफर और पोस्टिंग, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव (सीएल्यू) के मामलों और अन्य लेन-देन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। एजेंसी ने इन आरोपों के मिलसिले में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) राजबीर घुमन का नाम भी लिया था।

ये आरोप एक हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले और सीएल्यू की मंजूरी लेने में कथित अनियमितताओं की ईडी की जांच के दौरान सामने आए थे। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया में नकली सहमति पत्र इस्तेमाल किए गए थे और पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों को कथित भूमिका की ओर इशारा किया था।

पंजाब डीजीपी को भेजे गए पत्रों में ईडी ने यह भी कहा था कि प्राइवेट लोगों का एक नेटवर्क सरकारी प्रक्रियाओं, जैसे ट्रॉसफर और पोस्टिंग, पर प्रभावित करने में शामिल था। एजेंसी ने अपने पत्रों में नामजद लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, जब राज्य पुलिस ने एजेंसी के पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो वकील



निखिल सराफ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की।

इस पीआईएल में पंजाब पुलिस की कथित निष्क्रियता पर न्यायिक हस्तक्षेप और ईडी द्वारा उठाए गए आरोपों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को जांच के लिए केस सीबीआई को सौंप दिया।

इन आरोपों से पंजाब में जबरदस्त राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, और मान ने इन्हें बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। अगस्त में, मुख्यमंत्री ने कहा था कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और अपनी सरकार के खिलाफ किए जा रहे दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे।

मान ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी केन्द्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को बदनाम करने, धमकाने और दबाने के लिए किया जा रहा था।

विदेशी निवेश को लेकर

सरकार ने कसी कमर

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत दिसंबर तक कम से कम तीन और देशों के साथ बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने बताया कि कई देशों के साथ इस दिशा में बातचीत चल रही है और इसमें रूस भी शामिल है। अगर बातचीत तय दिशा में आगे बढ़ती रही तो दिसंबर तक तीन और देशों के साथ समझौते पूरे किए जा सकते हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सीतारमण ने कहा कि भारत कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश से जुड़े समझौतों पर बातचीत कर रहा है। बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट का उद्देश्य दोनों देशों के निवेशकों को एक-दूसरे के यहां निवेश के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल उपलब्ध कराना है।

इंडिगो ने फिट बढ़ाया फ्यूल चार्ज, हवाई सफर होगा महंगा

नई दिल्ली। हवाई सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर एक बार फिर असर पड़ने वाला है। इंडिगो ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की बढ़ती कीमतों के बीच घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। यह बदलाव 6 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। एयरलाइन के मुताबिक, पिछले महीने की तुलना में एटीएफ की कीमत में 14 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और इसकी लागत पिछले एक दशक के सबसे ऊंचे स्तरों में पहुंच गई है। बदकूती इंधन लागत की भरपाई के लिए इंडिगो ने दूरी के आधार पर घरेलू उड़ानों का फ्यूल चार्ज बढ़ाकर 375 रुपये से 1,300 रुपये प्रति सेक्टर कर दिया है। इंडिगो के अनुसार, हवाई इंधन के दाम में मासिक वृद्धि 14 फीसदी से अधिक हो गई है। हवाई इंधन एयरलाइन के परिचालन खर्च का एक बड़ा हिस्सा होता है। यह एयरलाइन की लागत संरचना और नेटवर्क अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है।

टोयोटा वाहनों की बिक्री पर उठे सवाल

नई दिल्ली। टोयोटा कलॉस्कर मोटर की जुलाई 2026 की घरेलू बिक्री के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आने के बाद कंपनी की बिक्री रिपोर्टिंग व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। कंपनी की वेबसाइट पर जुलाई में भारत में 17,456 वाहनों की घरेलू बिक्री बताई गई, जबकि इसी अवधि के लिए कंपनी की प्रेस व्रति्सि में घरेलू बाजार में 30,516 वाहन बेचने की जानकारी दी गई। दोनों आंकड़ों के बीच करीब 13,060 वाहनों का अंतर है। आंकड़ों में यह अंतर केवल टोयोटा की रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है। फाडा के वाहन पंजीकरण आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में देशभर में 29,443 टोयोटा वाहनों का पंजीकरण हुआ। यह संख्या कंपनी की वेबसाइट पर दिए गए 17,456 वाहनों के आंकड़े से काफी अधिक है।

स्टेल प्रमुख समाचार

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मैच आज

लखनऊ। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ मंगलवार को यहां होने वाले पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में आत्मविश्वास के साथ उतरेगी जिसमें मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए सबसे बड़ी दुविधा संजू सैमसन और युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से किसी एक का चयन करने को लेकर होगी। एशियाई खेलों में वीवीएस लक्ष्मण कोच थे और उन्होंने सैमसन और सूर्यवंशी दोनों को अंतिम एकादश में रखा था लेकिन अब गंभीर कोच हैं और ऐसे में रणनीतिक बदलाव होना तय है, भले ही दोनों कोच आठवें नंबर तक बल्लेबाजी रखने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर गंभीर की रणनीति को करीबी नजर से देखें तो वह सैमसन और सूर्यवंशी दोनों को एक साथ अंतिम एकादश में नहीं रखेंगे।

अभिषेक शर्मा सलामी बल्लेबाज के रूप पसंद बने हुए हैं। निशिन सिटी के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खराब पिचों पर लक्ष्मण ने इन तीनों बल्लेबाजों को टीम में रखा। सूर्यवंशी और विश्व के नंबर एक टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की, जबकि सैमसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। यह फैसला पिच की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। लेकिन लखनऊ के एकाना स्टेडियम की पिच पर गंभीर एक बार फिर सैमसन को सलामी बल्लेबाज के रूप में वापस लाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि निचले क्रम में ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का बैकअप मौजूद है। सैमसन नंबर तीन पर सहज नहीं दिखे। उन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में अफगानिस्तान के खिलाफ पिछली घरेलू टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में दो अर्धशतक बनाए थे। मध्य क्रम में पहले से ही कप्तान श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, युव कप्तान तिलक वर्मा, ऑलराउंडर शिवम दुबे और रेड्डी के साथ-साथ अक्षर पटेल भी मौजूद हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 472 अंक और निफ्टी 133 अंक उछलकर बढ़

नईदिल्ली। शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते की धमाकेदार शुरुआत हुई। बेंचमार्क इंडेक्स आधे-आधे फीसदी की बढ़त के साथ बढ़ हुए। सेंसेक्स 472.77 अंक उछलकर 72382 पर बढ़ हुआ। निफ्टी भी 133.80 अंकों की मजबूती के साथ 22555 पर बढ़ हुआ। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी स्मरूब, सरकारी बैंक समेत मीडिया शेयरों में देखने को मिली। डूझए 5ब से ज्यादा की मजबूती के साथ टॉप गेनर रहा। पिछले पूरे हफ्ते निवेशकों का भारी नुकसान करने वाले शेयर बाजार ने इस सप्ताह की शुरुआत बढ़त के साथ की। सोमवार को सेंसेक्स 472 अंक और निफ्टी 133 अंक उठकर बढ़ हुआ। शेयर बाजार के क्लोसिंग ऑक्शन सत्र में सेंसेक्स 402.53 अंक यानी 0.56 फीसदी बढ़कर 72,312.23 पर रहा। वहीं, निफ्टी50 113.50 अंक यानी 0.51 फीसदी की बढ़त के साथ 22,535.45 पर पहुंच गया।

विश्र्वास कैलाश सारंग

जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा की चमक को पूरी दुनिया ने देखा है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और जज्बे का शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती खेल शक्ति का परिचय कराया। तिरंगे की आन, बान और शान के लिए मैदान में उतरे हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में भारत को गौरवपूर्ण चौथा स्थान दिलाया। यह उपलब्धि केवल पदकों की संख्या नहीं बल्कि भारत की युवा बल्ल प्रतिभा के निरंतर निखरते सामर्थ्य और वैश्विक खेल मंच पर बढ़ते प्रभाव की स्थिति चमक है। वहीं इस प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने 10 मेडल जितमें 5 स्वर्ण, 4 रजत 1 कांस्य पदक अर्जित कर अपनी

सर्वोच्च प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर विशेष योगदान दिया है।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज खेल भारत की राष्ट्रीय प्रार्थमिकताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया जी के नेतृत्व में खेलों इंडिया जैसी योजना के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने, प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। छोटे शहरों, गांवों और सामान्य परिवारों से आने वाले युवा आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके पास अब केवल प्रतिभा नहीं बल्कि उसे निखारने के लिए अवसर, प्रशिक्षण और प्रतियस्पर्धी वातावरण भी उपलब्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का यह विजन कि भारत का युवा केवल



खेलों में भाग लेने वाला नहीं बल्कि दुनिया में भारत का नेतृत्व करने वाला बने, आज मैदानों में दिखाई दे रहा है। मिट्टी के मैदानों से लेकर आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक, स्कूलों से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तक, भारत की नई पीढ़ी खेलों को अपना भविष्य बनाने के लिए निरंतर आगे बढ़ रही है।

वहीं मध्यप्रदेश में भी हम प्रधानमंत्री जी के विजन को दृष्टिगत रखते हुए एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान के अनयन व विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में 18 खेलों की 11 अकादमी संचालित

हैं। इन अकादमियों में विश्व स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। नवीन सीएम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स योजना के तहत प्रदेश की सभी 230 विधानसभा में खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। खेलो एमपी यूथ गेम्स, पार्थ योजना, खेलो बढ़ो अभियान, टैलेंट सर्वे, समर कैंप सहित अन्य आयोजनों के माध्यम से नई प्रतिभाओं की तलाश और उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इस प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ियों ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर विश्व पटल पर राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। भारत के कुल पदकों में एथलेटिक्स का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसमें कुल 24 पदक जीते गए। इसके बाद शूटिंग का नंबर रहा, जिसमें 15 पदक मिले। इनमें तीन बार खिलाड़ी टॉप पोज़ियम पर रहे। बॉक्सिंग में भी तीन स्वर्ण पदक मिले, जिनमें लवलीन बोरोगेन भी शामिल थीं। आर्चरी में सबसे

ज्यादा पांच बार खिलाड़ी शीर्ष पोज़ियम पर रहे। अमन सहरावत और सुजीत कलकल ने रेसलिंग में एशियन गेम्स चैंपियन का खिताब जीता। भारत की महिला और पुरुष क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी टीमों ने गोल्ड मेडल हासिल किए। नौरू बंडा, कुमुकुम मोहोद, गुलवीर सिंह और विथ्या रामराज जापान में शामिल रहे, जिन्होंने पदक जीतने में योगदान दिया। सुचिका तरियाल ने महिला ट्रेडिशनल –60 किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मिस्सड मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला एशियन गेम्स पदक हासिल किया। सेमी-फाइनल में पहुंचने के बाद जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में भी वही कारनामा दोहराया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फ़ाइनल में श्रीलंका को हराकर अपना ख़िताब बरकरार रखा और इस टूर्नामेंट में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता।

जगदलपुर के जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री शर्मा

सुरक्षा और समृद्धि की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा बस्तर : विजय शर्मा

रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर अंचल नक्सलवाद के लंबे और काले दौर से निकलकर अब शांति, सुरक्षा और समृद्धि की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कभी हिंसा और भय से प्रभावित रहे क्षेत्रों में आज शासन की योजनाएं और सेवाएं पहुंच रही हैं। विकास के साथ लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास का नया वातावरण बन रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा आज जगदलपुर के पीडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर में शामिल हुए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा एक ही स्थान पर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने के साथ पात्र हितग्राहियों को वित्तीय सहायता, अधिकार अभिलेख, प्रमाण पत्र और विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

शिविर को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मां



दंतेश्वरी की कृपा और शासन-प्रशासन के साझा प्रयासों से बस्तर में माओवादी हिंसा समाप्ति की ओर है। क्षेत्र में अब भय के स्थान पर विश्वास और हिंसा के स्थान पर विकास एवं सेवा का नया सवेरा दिखाई दे रहा है। उन्होंने नक्सली हिंसा और आईईडी विस्फोटों से प्रभावित आम नागरिकों एवं सुरक्षा जवानों के पुनर्वास

का उल्लेख करते हुए कहा कि तीन दिवसीय विशेष शिविर के माध्यम से पीड़ितों और दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण शत-प्रतिशत नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस पहल से जुड़े एक भावुक प्रसंग का

उल्लेख करते हुए बताया कि कृत्रिम हाथ लगने के बाद एक हितग्राही ने उसी हाथ से पानी की बोतल उठाकर पानी पिया। वर्षों बाद अपने हाथ से सामान्य काम कर पाने की यह खुशी बताती है कि ऐसी पहल किसी व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है।

जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर में विभिन्न विभागों ने मौके पर ही पात्र हितग्राहियों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रदान किया। राजस्व विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पांच बाढ़ प्रभावितों को कुल 6 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके साथ ही 35 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए गए। श्रम विभाग द्वारा मिनीमाता महतारी जलन योजना के अंतर्गत एक हितग्राही को 20 हजार रुपये तथा मुख्यमंत्री मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत एक पात्र हितग्राही को एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।

घर बैठे वाहन संबंधी आवश्यक कार्य पूर्ण करने की मिलेगी सुविधा : केदार कश्यप

जिले में अत्याधुनिक वाहन टैरिंटिंग की सुविधा जल्द

प्रारंभ होगी : टंक राम वर्मा



बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप ने सोमवार को बलौदाबाजार के ग्राम पंचायत परसाभदेर में नवनर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन का विधिवत लोकार्पण किया। राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को नया आयाम देने के उद्देश्य से सोनबरसा जंगल सफारी के लिए 4 नई जिप्सियों और परिसर के सौंदर्यीकरण तथा अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 1.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

लोकार्पण के पश्चात मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सर्वसुविधायुक्त नवनर्मित जिला परिवहन कार्यालय

भवन के विभिन्न कक्षों का अवलोकन किया। मंत्रीद्वय ने भवन की उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्माण शैली की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए अधिकारियों को आम जनता की सहूलियत और नागरिक केंद्रित सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया।

समारोह को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार जन-आकांक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए परिवहन सेवाओं का तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है। आने वाले समय में परिवहन विभाग से जुड़े सभी कार्य पूरी तरह डिजिटल प्रणाली पर आधारित होंगे, जिससे नागरिकों को अपने आवश्यक कार्य

घर बैठे ही पूर्ण करने की अभूतपूर्व सुविधा मिलेगी। जिले में पंजीकृत 2 लाख 14 हजार से अधिक वाहनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने यातायात नियमों के पालन पर विशेष बल दिया। विशेषकर स्कूली बच्चों द्वारा वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करें ताकि संभावित दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए संचालित श्रावहीर योजनाशू का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत पीड़ितों को डेढ़ लाख रुपये तक के मुफ्त एवं कैशलेस इलाज की व्यवस्था दी जा रही है।

भाजपा के लिये ओबीसी सिर्फ वोट बैंक है, जनगणना से लेकर आरक्षण तक वादाखिलाफी : दीपक बैज

रायपुर। भाजपा सरकार पर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय और विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा के लिए ओबीसी सिर्फ वोट बैंक है, जब गिनती की बात आती है तो फॉर्म से गायब, जब हक की बात आती है तो राजभवन में फाइल दबा दी जाती है। जो भाजपा चुनाव में ओबीसी का नाम जपकर वोट मांगती है, सत्ता में आते ही उसी समाज के पीट पर छुरा घोंपने का काम करती है। एक तरफ राष्ट्रीय जनगणना के फॉर्म से ओबीसी की गिनती का स्पष्ट कॉलम गायब कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की विधानसभा द्वारा पारित

27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण बिल को 2 दिसंबर 2022 से आज तक दबाकर रखा गया है। भाजपा का सिद्धांत है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ओबीसी का, अधिकार दोगे दूसरों को? प. दे. श. कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा ओबीसी कल्याण और सबका विकास का दावा करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ओबीसी की आबादी लगभग आधे से अधिक है, फिर भी राज्य में 27 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक को कानून बनाने में टालमटोल की जा रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार

के दौरान सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा पारित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के माध्यम से रोड़ा अटकाना और केंद्र स्तर पर जनगणना में ओबीसी के लिए स्पष्ट कॉलम शामिल न करना, जातिमें की ड्रॉप डाउन सूची न होना यह दर्शाता है कि भाजपा की नीति केवल वोटों तक सीमित है, संवैधानिक अधिकारों तक नहीं। जनगणना फार्म में सटीक और पारदर्शी गिनती के लिए सवाल नंबर 10 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरह ही एक अलग और स्पष्ट ओबीसी कॉलम अनिवार्य करे सरकार, जिससे ओबीसी वर्ग की पृथक गिनती हो सके।

कुगदा गेट समपार फाटक स्थायी रूप से बंद

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत कुम्हारों-सी केबिन के मध्य लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 430 (कुगदा गेट) को 5 अक्टूबर से सड़क यातायात के लिए स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कुगदा गेट पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है आरयूबी के माध्यम से सड़क यातायात की स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 430 को नियमानुसार स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। 5 अक्टूबर के बाद लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 430 (कुगदा गेट) से किसी भी प्रकार का सड़क आवागमन नहीं किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री साव सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर में हुए शामिल

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव गुजरात के नर्मदा में आज से शुरू हुए सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर में शामिल हुए। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गतिशील से प्रगति थीम पर इसका आयोजन किया गया है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा भी इस दौरान मौजूद थे। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सड़क निर्माण से जुड़े विभागों के मंत्री, अधिकारी, विशेषज्ञ एवं नीति निर्माता इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर में भागीदारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की ओर से उप मुख्यमंत्री श्री साव के साथ लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के.



भतपहरी, अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव और राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री ज्ञानेश्वर कश्यप भी चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे हैं।

चिंतन शिविर में भाग ले रहे विभिन्न राज्यों के मंत्रियों, अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं नीति निर्माताओं ने आज तीन सत्रों में भविष्य में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की डिजाइन, गुणवत्ता, रोड सेफ्टी और परियोजना प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर

से जगदलपुर, बिलासपुर से रायगढ़, कटघोरा से अंबिकापुर और रायपुर से सारंगढ़ तक फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्गों की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है। चिंतन शिविर में निर्धारित किए जाने वाले फ्रेमवर्क्स से इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय चिंतन शिविर के पहले दिन आज विभिन्न सत्रों में पीएम गतिशील—सर्मान्वत और प्रभावी परियोजना क्रियान्वयन के लिए एकीकृत अधोसंरचना नियोजन, भूमि अधिग्रहण में तेजी और भूमि राशि का प्रभावी उपयोग तथा सुदृढ़ परियोजना क्रियान्वयन और रेंटिंग के लिए मॉडल कसेशन एग्रीमेंट फ्रेमवर्क पर गहन विचार-विमर्श किया गया। चिंतन शिविर के दूसरे दिन 6 अक्टूबर को सुरक्षित राजमार्गों का डिजाइन—मार्गकों से क्रियान्वयन तक और गुणवत्ता आश्वासन एवं परियोजना मॉनिटरिंग पर मंथन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

नगर निगम व जनों के अधिकारियों को दी गई नवीन पदस्थापना

रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त सचिव मिश्रा ने आदेश जारी करते हुए नगर पालिक निगम सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक रायपुर नगर पालिक निगम मुख्यालय एवं जनों के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना कर दी है। रायपुर नगर निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार पदमाकर श्रीवास कार्यपालन अभियंता मुख्यालय से जौन क्रमांक 15, लाल मेहेंद्र प्रताप सिंह कार्यपालन अभियंता जौन क्रमांक 5 से जौन क्रमांक 6, दिनेश कुमार सिन्हा कार्यपालन अभियंता जौन क्रमांक 6 से जौन क्रमांक 10, गजाराग कंवर कार्यपालन अभियंता जौन क्रमांक 10 से मुख्यालय (उद्यान शाखा), श्री शत्रुघ्न देशलहरे सहायक अभियंता जौन क्रमांक 7 से जौन क्रमांक 8, दीपक देवानंन सहायक अभियंता जौन क्रमांक 4 से प्रभारी कार्यपालन अभियंता मुख्यालय से जौन क्रमांक 4, संस्कार शर्मा सहायक अभियंता मुख्यालय से महापौर कार्यालय, 15 वां वित्त आयोग एवं उद्यान शाखा, वसीम खान उप अभियंता जौन क्रमांक 10 से प्रभारी सहायक अभियंता (स्वच्छ भारत मिशन), श्रीमती अर्जिता दीवान उप अभियंता मुख्यालय से प्रभारी सहायक अभियंता जौन क्रमांक 7, योगेन्द्र साहु उप अभियंता जौन क्रमांक 8 से मुख्यालय (योजना शाखा, 15 वां वित्त एवं लोक कर्म विभाग) में पदस्थ कर किए गए हैं।

प्रदेश की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था के कारण : कांग्रेस

रायपुर। बालोद में एक छात्रा के ऊपर एसिड अटैक की कांग्रेस ने कड़ी निंदा करते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह प्रदेश की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था का बेहद ही क्रूर उदाहरण है। प्रदेश में अब बेटीयां भी सुरक्षित नहीं हैं। छात्रा लाइब्रेरी से पढ़ाई करके घर वापस जा रही थी, उसके ऊपर एसिड से हमला किया गया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गयी है। यह घटना बेहद ही चिंता का विषय है। गुहमंत्री इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी ले और तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश अपराध का गढ़ बन चुका है। राज्य में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश में हर दिन 8 महिलाएं दुराचार का शिकार हो रही हैं अर्थात् हर तीन घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार की घटना हो रही है। महिलाओं को घर में घुसकर गोली मारी जा रही, राजधानी में गैंगरेप हो जाता है, एसिड अटैक हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बालोद में एसिड अटैक यह घटना सामान्य नहीं है। इस घटना ने पूरे को झकझोर कर रख दिया है।

अब जरूरी दस्तावेजों के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चकर: गजेन्द्र बिलासपुर।

विद्यार्थियों और अभिभावकों को शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़े कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी न हो और उन्हें अपने जरूरी दस्तावेज समय पर मिल सकें, इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने पहल की है। मंत्री के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध किए जाने की व्यवस्था की गई है। इससे विद्यार्थियों को अपने जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या से राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन तथा उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी जैसी सेवाएं निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। दस्तावेज के अनुसार इन सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा भी तय की गई है। डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र और डुप्लीकेट अंकसूची के लिए 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित है। वहीं उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और फोटोकॉपी से संबंधित सेवाओं के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के बाद 60 दिवस की समय-सीमा रखी गई है।

पौने तीन साल की सरकार में ही भाजपा में भगदड़ : कांग्रेस रायपुर।

भाजपा के नये संगठन महामंत्री के सामने पार्टी की गुटबाजी बड़ी चुनौती है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि छह साल में ही भाजपा सरकार के सारे दावे खोखले निकले भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता सरकार के क्रियाकलापों से बेहद खफा एवं नाराज है। सरकार में बैठे नुमाइंदों के व्यवहार, कार्यकर्ताओं को सरकार में पद की उम्मीद नहीं करने की हिदायत एवं चंद लोग जो 15 साल के सत्ता के दौरान मलाई खाये वही लोगो को निगम मंडल आयोग में पुनः नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। भाजपा कार्यकर्ता भी सरकार की नाकामी उपेक्षा जनविरोधी रवैये से नाराज है। डोंगरगढ़, रायगढ़ के चुसीर, बीजापुर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता ने पार्टी और सरकार की कार्यशैली से नाराज हो कर पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके पहले भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि भागत एवं पाषंदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब भाजपा का अंतर्कलह खुल कर सामने आ रहा है। एल्डरमैन की नियुक्ति पैसा लेकर करने का आरोप भाजपा नेताओं पर लग रहा है। पूरा प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता से नाराज है। भाजपा कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ना बताया है कि सरकार कितनी अलोकप्रिय हो चुकी है।

26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता कल बिलासपुर।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव 7 अक्टूबर को 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन समारोह सुबह 10.30 बजे स्व. बी.ओर. यादव राज्य प्रशिक्षण केंद्र, बहताराई में आयोजित होगा। जिले में 7 से 10 अक्टूबर तक आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्कूली खिलाड़ी तीरंदाजी, हॉकी और कबड्डी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, तखतपुर विधायक मंजीत सिंह, बेलतरा विधायकसुशान्त शुक्ला, मस्तुरी विधायक दिलीप लहरिया, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पाण्डेय, क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सक्ती, बिलासपुर महापौर श्रीमती पूजा विधानी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। श्री दीपक सिंह ठाकुर एवं मोहित जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। प्रतियोगिता के अंतर्गत तीरंदाजी में 14, 17 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिका, हॉकी में 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक हिस्सा लेंगे।

शासन की योजनाओं से आमजन के जीवन में आया बदलाव : क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सक्ती जरूरतमंदों तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ : कौशिक

बिलासपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत जनपद पंचायत बिल्हा के ग्राम हरदी में आज सेवा सेतु शिविर का आयोजन बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक के मुख्य अतिथ्य में किया गया। शिविर में क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सक्ती, जनपद पंचायत अध्यक्ष डॉ. रामकुमार कौशिक, उपाध्यक्ष श्री विक्रम सिंह ठाकुर, बिल्हा नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वंदना जेष्ठे, जनपद सदस्य श्रीमती सरस्वती यादव, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल भी शामिल हुए। विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए गए। शिविर में प्राप्त कुल 87 आवेदनों में से 44 का निराकरण किया गया। शिविर में हितग्राहियों को विभिन्न योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया।



विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि सेवा सेतु शिविर का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आवास, रसोई गैस, पेयजल और बिजली जैसी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए

निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। सेवा सेतु शिविरों के माध्यम से जरूरतमंदों को इन योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। श्री कौशिक ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जनसेवा और जनभागीदारी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 'आशीर्वाद का दीया', आंगनबाड़ी केंद्रों में

कार्यक्रम तथा विद्यालयों में चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में सेवा सेतु शिविरों से नागरिकों को उनके नजदीक शासकीय सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।

क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सक्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से आमजन के जीवन में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिला है। शौचालय निर्माण से स्वच्छता के साथ गरिमा और जनधन खातों से बैंकिंग सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

दुर्ग। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम सेलूद में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने राष्ट्रीय पोषण माह के तहत नवजात शिशुओं की माताओं एवं गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार किट वितरित कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया।

इस अवसर पर मंत्री श्री यादव ने कहा कि स्वस्थ मां और स्वस्थ बच्चे ही सशक्त समाज की मजबूत नींव हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक



विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे के अच्छे संस्कार और व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं का स्वस्थ, प्रसन्न और सकारात्मक वातावरण में रहना बेहद जरूरी है।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि पहले गर्भ संस्कार की परंपरा

परिवार के स्तर पर निभाई जाती थी, अब शासन भी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए गर्भवती महिलाओं के बेहतर पोषण पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी उद्देश्य से महिलाओं को पौष्टिक आहार किट उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने पुंसवन संस्कार, गोद भराई, अन्नप्रशाला और स्वस्थ शिशु जैसी गतिविधियों को माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं जागरूकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। शिक्षा मंत्री श्री यादव ने लोगों से पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में नशे से दूर रहने का संकल्प लेने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।